भारतीय रेल

मई 2025

मूल्य ₹20



नया पांबन

विकसित भारत का सेतु

प्रधानमंत्री ने की रामेश्वरम-ताम्बरम नई ट्रेन सेवा की शुरूआत

मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ने वाला नया पांबन ब्रिज

AAL® Autometers Alliance Ltd



POWER ELECTRONICS & PROPULSION SYSTEM

DATA ACQUISITION AND CONTROL DEVICE

TRACTION SWITCHGEAR AND PANELS

DISPLAY AND PASSENGER INFORMATION SYSTEM

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES

POWERING THE **RAIL TRANSPORT** EFFICIENTLY AND INTELLIGENTLY

ENERGY & EFFICIENCY
SAFETY & RELIABILITY

Pegasus ◆ UPS®



MAKE IN INDIA COMPANY

ISO 9001:2015
14001:2015
45001:2018

C-63, Sector-57, Noida - 201 307 (U.P.) India, mktre@autometers.com, www.autometers.com

भारतीय रेल

रेल मंत्रालय की एकमात्र हिंदी मासिक पत्रिका

आरंभ: अगस्त-1960 वर्ष: 65 अंक: 10 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित पत्रिका मई-2025 मूल्य: ₹20

संपादक मंडल

सतीश कुमार
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड

उषा वेणुगोपाल
सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

अरुणा नायर
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिलीप कुमार
कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं प्रचार

शिवाजी मारुती सुतार
निदेशक, सूचना एवं प्रचार

योगेश अवस्थी
संपादक

संपादकीय कार्यालय
संपादक, भारतीय रेल,
कमरा नं. 411, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
editorbhartiyarailrb@gmail.com
editorbhartiyarail@gmail.com

विज्ञापन व सदस्यता हेतु संपर्क
ललित कुमार धनकड़
व्यापार प्रबंधक
कमरा नं. 310, रेल भवन
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन: 011-47845378, 47845089
bmpr310rb@gmail.com

आवरण
नया पांबन ब्रिज

फॉलो करें
Twitter :
@bhartiyarailrb

वार्षिक सदस्यता शुल्क
(ऑफलाइन)
सर्वसाधारण-₹250
रेलकर्मियों के लिए -₹200
विदेश में
सी-मेल द्वारा -₹1,250
एयर-मेल द्वारा -₹2,500
एक प्रति-₹20 वार्षिक विशेषांक-₹70

इस पत्रिका में छपी हर सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषत: स्पष्ट न लिखा जाए, किसी सरकारी सूत्र से न समझा जाए।

© भारतीय रेल

8 प्रधानमंत्री ने नया पांबन ब्रिज किया राष्ट्र को समर्पित

11 प्रधानमंत्री ने बिहार को दी तीन नई रेल लाइनों और चार ट्रेनों की सौगात

15 प्रधानमंत्री, भारत द्वारा श्रीलंका की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन

16 कैबिनेट ने पांच प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

18 अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश को मिली नई ट्रेन

19 भारतीय रेल मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में बेहतर सेवाएँ : रेल मंत्री

22 सबसे लंबी रेल सुरंग - टनल नं. 8 का सफल ब्रेकथ्रू

25 रेल राज्य मंत्री द्वारा आरओबी का निरीक्षण

27 भारतीय रेल ने प्राप्त किया ₹2.56 लाख करोड़ का राजस्व

31 भारतीय रेल ने पारदर्शी राजस्व निगरानी की डिजिटल व्यवस्था

32 भारतीय रेल द्वारा 2,249 स्टेशनों पर 209 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित

33 लोकोमोटिव उत्पादन में अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकला भारत

34 वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने बनाए 7,134 नए कोच

35 वित्त वर्ष 2024-25 में रेल वैगन का रिकॉर्ड उत्पादन

36 क्या आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है ?

40 भारतीय रेल ने बढ़ाई गति तथा क्षमता दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बहु-रेल लाइन, डीएफसी का किया विस्तार

42 मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निर्बाध कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़े शहर, मजबूत अर्थव्यवस्था को मिली गति

45 क्षेत्रीय रेल एवं उत्पादन इकाइयों के समाचार

47 प्रगति रिपोर्ट

52 अमृत भारत स्टेशन योजना

54 खेलों में भारतीय रेल

58 समय और विरासत की एक यात्रा — बी. राधा रानी

61 कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन : एक जटिल एवं खूबसूरत रेल लाइन — विमलेश चंद्र

65 चिनाब रेल ब्रिज : राष्ट्र की संकल्प गाथा का अनमोल अध्याय — दिलीप कुमार

68 भारतीय ज्ञान पद्धति की प्रशासनिक उपयोगिता — डॉ. अच्युतानन्द झा

संपादकीय



भारतीय रेल ने 172 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा पूरी कर ली है। यह यात्रा केवल लोहे की पटरियों और इंजनों की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, उम्मीदों और सपनों की कहानी है। इस दीर्घकालिक सफर में भारतीय रेल ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उसका ध्येय सदैव एक रहा-देशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और विश्वसनीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना।

पिछले एक दशक में भारतीय रेल ने जिस रफ्तार से विकास की पटरी पर कदम बढ़ाया है, वह 'नए भारत' के आत्मविश्वास का परिचायक है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली योजनाओं ने भारतीय रेल को वैश्विक मानकों के समकक्ष ला खड़ा किया है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज परियोजना, बुलेट ट्रेन, पांबन ब्रिज और समर्पित मालवाहक गलियारे (डी.एफ.सी.) जैसी योजनाएँ भारत की सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक मजबूती की आधारशिला हैं। ये परियोजनाएँ न केवल बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी समृद्धि लाने का कार्य कर रही हैं, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर थे।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के अंतर्गत पांच मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे 1,360 कि.मी. लंबा नेटवर्क विकसित होगा। लगभग ₹19,900 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इन पाँच परियोजनाओं से न केवल 61 लाख से अधिक लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल संख्या 8, सौड-जनासु सुरंग का ब्रेकथ्रू दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को हुआ, जिससे यह भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई। यह परियोजना उत्तराखंड के पाँच पर्वतीय जिलों को जोड़ती है और 83 प्रतिशत मार्ग सुरंगों से होकर गुजरता है, जो इसकी तकनीकी जटिलता को दर्शाता है। यह केवल एक इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और लक्ष्य है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी सशक्त कनेक्टिविटी पहुँचे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2025 को राष्ट्र को समर्पित नया पांबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी-ब्रिज है, जो आधुनिकता, नवाचार और इंजीनियरिंग दक्षता का अद्भुत उदाहरण है। इसका 72 मीटर लंबा सेंट्रल स्पैन पानी से 22 मीटर ऊपर उठता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से इसके नीचे से गुजर सकते हैं। रेल यातायात के दौरान ब्रिज के दोनों सिरे सुरक्षित रूप से जुड़ जाते हैं। 100 साल से अधिक पुराने ब्रिज के समानांतर इसका निर्माण किया गया है।

भारतीय रेल आज सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की धड़कन बन चुकी है।

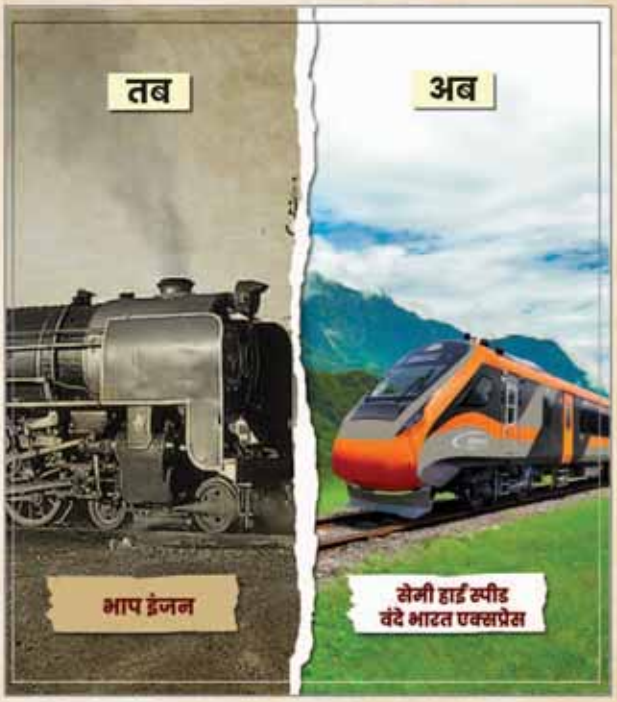
आपको हमारा यह अंक कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं।

भारतीय रेल के

172 वर्ष

कल और आज : रूपांतरण का स्वर्णिम सफर







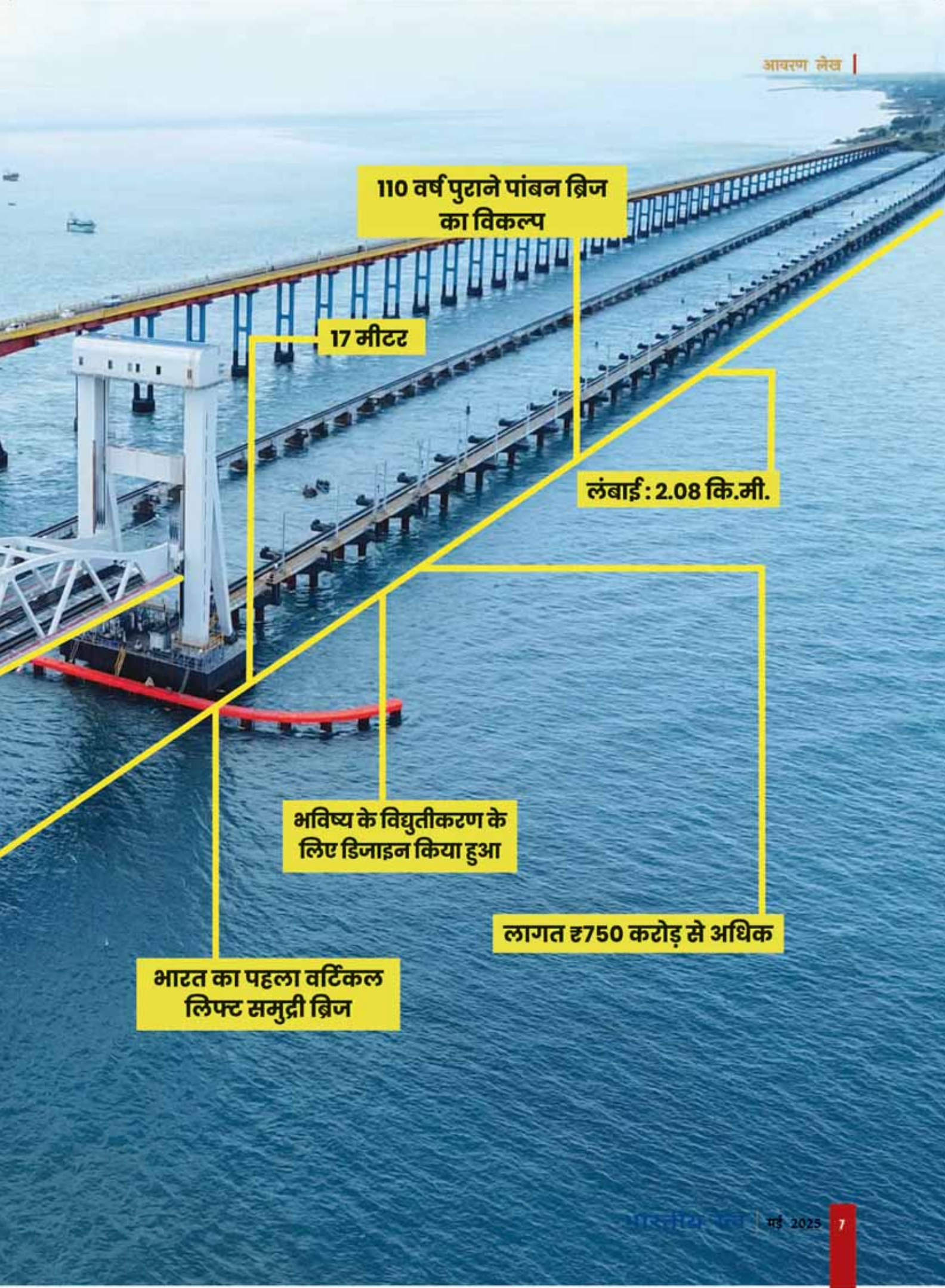


नया पांबन ब्रिज

विकसित भारत

का प्रतीक




110 वर्ष पुराने पांबन ब्रिज का विकल्प
17 मीटर
लंबाई : 2.08 कि.मी.
भविष्य के विद्युतीकरण के लिए डिजाइन किया हुआ
लागत ₹750 करोड़ से अधिक
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज

प्रधानमंत्री ने

नया पांबन ब्रिज

किया राष्ट्र को समर्पित

सांस्कृतिक महत्त्व की नई ट्रेन सेवा रामेश्वरम-ताम्बरम (चेन्नई) को दिखाई हरी झंडी



नया पांबन ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,
मंच पर उपस्थित हैं तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 6 अप्रैल, 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में ₹8,300 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इससे पहले, उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज- नए पांबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और सड़क ब्रिज से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई और ब्रिज का संचालन देखा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम-ताम्बरम (चेन्नई) नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।



इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के संगम युग के साहित्य में भी भगवान श्री राम का उल्लेख है। उन्होंने रामेश्वरम की पवित्र धरती से श्री राम नवमी के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

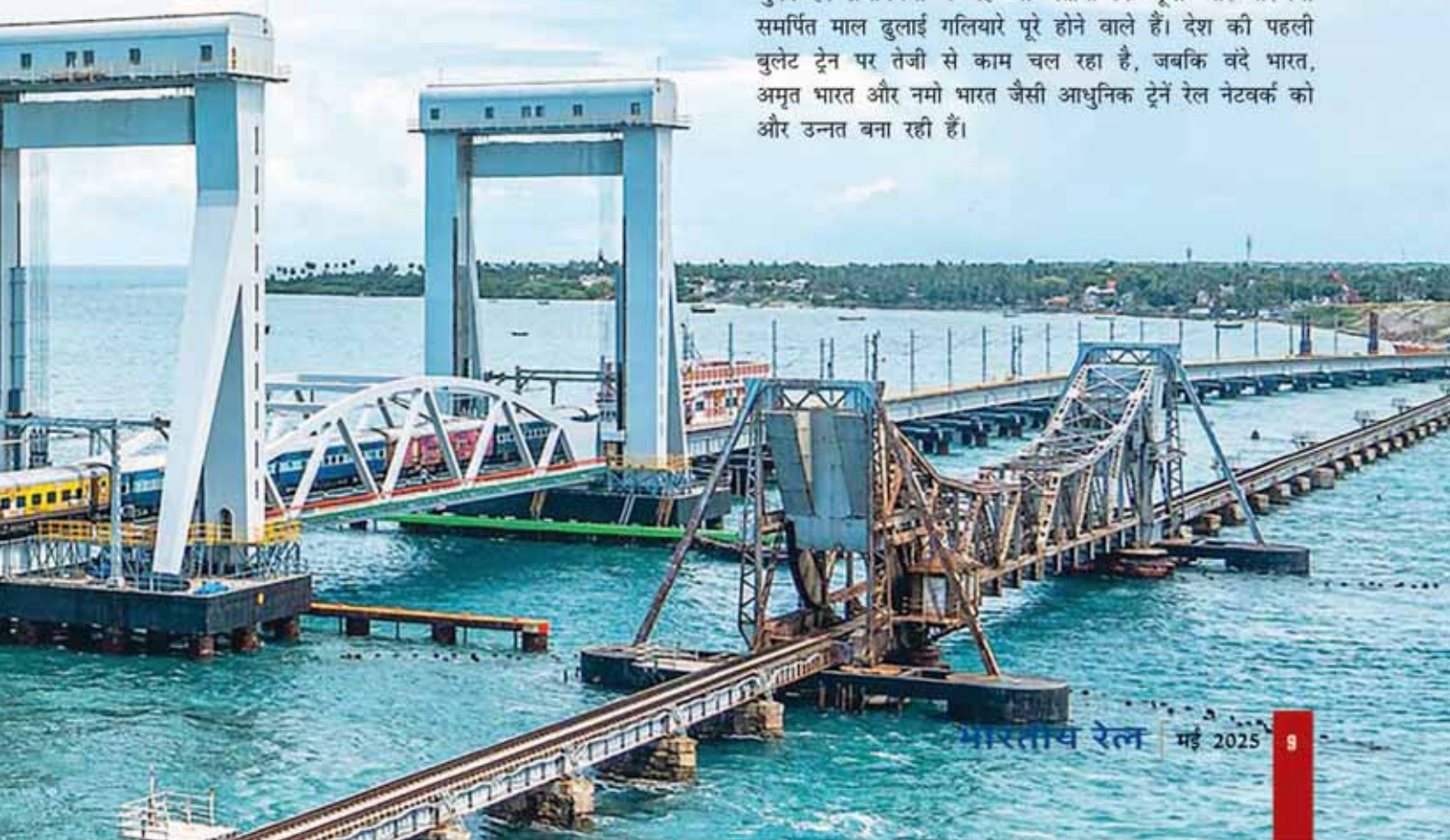
उन्होंने कहा कि रामेश्वरम भारत रत्न डॉ. कलाम की भूमि है, जिनके जीवन ने दिखाया कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'रामेश्वरम के लिए नया पांबन ब्रिज प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक है।' हजारों साल पुराना एक शहर अब 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार से जुड़ गया है। उन्होंने इंजीनियरों और श्रमिकों के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री ब्रिज है, जो बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है और साथ ही तेज ट्रेन यात्रा को सक्षम बनाता है।

इस बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की मांग दशकों से चली आ रही थी। लोगों के आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पांबन ब्रिज व्यापार और यात्रा दोनों को आसान बनाएगा, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई ट्रेन सेवा रामेश्वरम से चेन्नई और देश के अन्य हिस्सों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। इस विकास से तमिलनाडु में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है।' इस विकास का एक प्रमुख कारण



देश का उल्लेखनीय आधुनिक बुनियादी ढाँचा है। पिछले दशक में रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढाँचे के लिए बजट में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, 'आज, देश भर में मेगा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।' उत्तर में, जम्मू और कश्मीर में चिनाब ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो दुनिया के सबसे ऊँचे रेल ब्रिजों में से एक है। पश्चिम में, मुंबई अब देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज, अटल सेतु का घर है। पूर्व में, असम में बोगीबील ब्रिज प्रगति का प्रमाण है, जबकि दक्षिण में, दुनिया के कुछ वर्टिकल लिफ्ट ब्रिजों में से एक, पांबन ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पूरे होने वाले हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और उन्नत बना रही हैं।



इस बात पर बल देते हुए कहा कि जब भारत का हर क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़ता है, तो विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग मजबूत होता है, दुनिया भर के हर विकसित देश और क्षेत्र में ऐसा ही हुआ है। जैसे-जैसे भारत का हर राज्य जुड़ता है, देश की पूरी क्षमता का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि इस कनेक्टिविटी से तमिलनाडु सहित देश के हर क्षेत्र को फायदा हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में तमिलनाडु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।' जैसे-जैसे तमिलनाडु की क्षमता बढ़ती जाएगी, भारत का विकास और भी तेज होगा। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से पहले की अवधि की तुलना में तमिलनाडु के विकास के लिए तीन गुना अधिक धनराशि आवंटित की है। इस बढ़ी हुई धनराशि ने तमिलनाडु के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में बुनियादी ढाँचे का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है, पिछले एक दशक में तमिलनाडु का रेल बजट सात गुना से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2014 से पहले तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं को सालाना केवल ₹900 करोड़ मिलते थे, जबकि इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट ₹6,000 करोड़ से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है, जिसमें रामेश्वरम स्टेशन भी शामिल है।

पांबन ब्रिज का गहरा सांस्कृतिक महत्त्व है। रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह ब्रिज वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप



में खड़ा है। इसे ₹700 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 कि.मी. है, इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊँचाई तक उठता है, जिससे जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा मिलती है और साथ ही निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित होता है। स्टेनलेस स्टील सुदृढीकरण, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट और पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों के साथ निर्मित, ब्रिज में अधिक स्थायित्व और कम रखरखाव की आवश्यकता है। इसे भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष पॉलीसिलोक्सीन कोटिंग इसे जंग से बचाती है, जिससे कठोर समुद्री वातावरण में दीर्घायु सुनिश्चित होती है।



रामेश्वरम-ताम्बरम (चेन्नई) नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

प्रधानमंत्री ने बिहार को दी तीन नई रेल लाइनों और चार ट्रेनों की सौगात

- ₹869 करोड़ की रेल परियोजनाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी गति
- बिहार को मिली पहली नमो भारत रैपिड रेल और दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले से वर्चुअल माध्यम से राज्य को रेल विकास की अनेक सौगातें दीं। इस अवसर पर ₹869 करोड़ की लागत वाली तीन रेल परियोजनाएँ-सुपौल-पिपरा नई रेल लाइन, हसनपुर-बिथान नई रेल लाइन और खगड़िया-अलौली नई रेल लाइन-राष्ट्र को समर्पित की गईं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें जयनगर-पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल, सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच अमृत भारत ट्रेन, पिपरा-सहरसा तथा सहरसा-समस्तीपुर के बीच दो नई ट्रेन सेवाएँ शामिल हैं।

इन रेल परियोजनाओं और सेवाओं ने सुपौल, सहरसा, खगड़िया और मधुबनी जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया है। इनसे न केवल ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, बल्कि विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सहरसा और मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच शुरू हुई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' देश की तीसरी और बिहार की दूसरी ट्रेन है, जो यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। वहीं, जयनगर और पटना के बीच शुरू हुई 'नमो भारत रैपिड रेल' बिहार की पहली रैपिड रेल सेवा है और अहमदाबाद-भुज के बाद यह देश की दूसरी नमो भारत सेवा बनी है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, 'भारत रेलवे, सड़क और हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।' उन्होंने यह भी बताया कि पटना में मेट्रो परियोजनाएँ प्रगति पर हैं और देश भर के दो दर्जन से अधिक शहर अब मेट्रो सुविधाओं से जुड़ चुके हैं। जयनगर और पटना के बीच 'नमो भारत रैपिड रेल' सेवा से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इस विकास से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने सहरसा और मुंबई के बीच शुरू हुई 'अमृत भारत ट्रेन' सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे श्रमिक परिवारों को बहुत लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार मधुबनी और झंझारपुर सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है। उन्होंने कहा, 'ये विकास परियोजनाएँ बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।' इन सभी परियोजनाओं से राज्य में रेल संपर्क मजबूत होगा और गाँवों की सीधी पहुँच शहरों के कॉलेजों, अस्पतालों और बाजारों तक बनेगी। ये परियोजनाएँ विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं।



रेल परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मंच पर उपस्थित थे- बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, राम नाथ ठाकुर और डॉ. राज भूषण चौधरी

अमृत भारत एक्सप्रेस

22 कोच वाले रेक के दोनों छोर इंजनों से जुड़े हैं

गति क्षमता: 130 कि.मी./घंटा

संस्करण-1

लोको+1 एलएसएलआरडी+4 एलडब्ल्यूएस+12 एलडब्ल्यूएससीएन+4 एलडब्ल्यूएस+1 एलएसएलआरडी+लोको

मात्रा : 2024 में 2 रेक

संस्करण-2

लोको+1 एलएसएलआरडी+5 एलडब्ल्यूएस+4 एलडब्ल्यूएससीएन+1 एलडब्ल्यूसीबी+4 एलडब्ल्यूएससीएन+6 एलडब्ल्यूएस+1 एलएसएलआरडी+लोको

मात्रा : 2025 में 25 रेक

- पुश-पुल संचालन के लिए दोनों छोरों पर इंजनों के साथ कंट्रोल कपलर्स
- जर्क-फ्री यात्रा के लिए सेमी-पर्मानेंट कपलर्स-संस्करण-1
- सेमी-ऑटोमैटिक कपलर्स के साथ जर्क-फ्री यात्रा और आसान कनेक्शन/डिस्कनेक्शन-संस्करण-2

यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ

- फोल्ड करने योग्य स्नैक टेबल
- फोल्डेबल बोतल होल्डर
- रेडियम से प्रकाशित फ्लोरिंग स्ट्रिप
- एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बोगियाँ
- मोबाइल होल्डर
- बेहतर सीटें और बर्थ
- तेजस प्रकार का सील्ड गैंगवे (वेस्टिब्यूल)
- प्रत्येक कोच में 2 भारतीय और 2 पश्चिमी शैली के शौचालय, इलेक्ट्रो-पन्यूमैटिक फ्लशिंग सिस्टम,
- स्वचालित साबुन डिस्पेंसर
- शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली
- प्रत्येक यात्री के लिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट
- पब्लिक एड्रेस और यात्री सूचना प्रणाली (पीएपीआईएस)
- स्ट्रीमलाइन्ड-एलईडी लाइट फिटिंग
- स्लीपर कोच में एक दिव्यांगजन शौचालय
- शौचालय संकेत प्रकाश
- एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल्स के साथ संशोधित आंतरिक पैनलिंग



अमृत भारत संस्करण 2.0 में अतिरिक्त सुविधाएँ

- सेमी-ऑटोमैटिक कपलर्स, सेमी-पर्मानेंट के स्थान पर आसानी से जोड़ने और हटाने के लिए।
- दुर्घटना से सुरक्षा देने वाली विशेषताएँ।
- त्वरित ब्रेक आवेदन के लिए इलेक्ट्रो-पन्यूमैटिक सहायक ब्रेक सिस्टम।
- तेजी से जोड़ने और हटाने के लिए पूरी तरह से सील्ड गैंगवे।
- वंदे भारत के समान शौचालयों के लिए वैक्यूम निकासी प्रणाली।
- एसएमसी (शीट मोल्डिंग कम्पाउंड) सामग्री वाले शौचालय ताकि रखरखाव में सुविधाजनक और उपयोगी हो।
- स्लीपर कोच में एक दिव्यांगजन शौचालय।
- शौचालय संकेत प्रकाश।
- एफआरपी मॉड्यूलर शौचालय, जिसमें स्वचालित स्वच्छता की व्यवस्था और दुर्गंध नियंत्रण प्रणाली।
- व्हील और बेयरिंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑन-बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओबीसीएमएस)।
- आईओटी आधारित जल स्तर संकेतक-इंटरनेट आधारित जल स्तर संकेतक जो पानी भरने वाले स्टेशन और ऑन-बोर्ड स्टाफ की सहायता करते हैं।
- बाहरी आपातकालीन रोशनियाँ जो आपातकालीन स्थितियों जैसे डिरलमेंट और दुर्घटनाओं में बुनियादी रोशनी प्रदान करती है।
- चार्जिंग सॉकेट्स-ए और सी प्रकार के पोर्ट के लिए यूएसबी।
- एसएस ग्रिल्स के साथ पंखे।
- स्ट्रीमलाइन्ड-एलईडी लाइट फिटिंग।
- पब्लिक एड्रेस और यात्री सूचना प्रणाली।
- तेजस की तरह गैंगवे।
- शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली।



नमो भारत रैपिड रेल

यह 16 कोच वाली ट्रेन है, जो 110 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा कर सकती है

प्रमुख विशेषताएँ

- नई पीढ़ी की हल्की बोगियाँ पूरी तरह से सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर्स के साथ।
- 50% पावरिंग (मोटरयुक्त प्रत्येक वैकल्पिक कोच)।
- ट्रैक्शन मोटर्स के लिए नई बेहतर वेंटिलेशन डक्टिंग।
- व्हील-माउंटेड डिस्क ब्रेक्स।
- रिजेनरेटिव (पुनः ऊर्जा उत्पन्न करने वाला) ब्रेकिंग सिस्टम।
- एरोडायनैमिकली (वायुगतिकी रूप से) आकार वाले चालित छोर।
- स्वचालित डबल लीफ प्लग दरवाजे।
- कोचों के बीच चौड़े और सील किए गए दो-परत गैंगवे।
- कोचों के बीच पूर्ण सेतु वाला रास्ता।
- सभी प्रणोदन उपकरण कोच के नीचे।
- स्थायी तौर पर सील की गई खिड़कियाँ।
- बेहतरीन आंतरिक सजावट।
- 3 X 3 सीटिंग लेआउट और खड़े होने वालों के लिए हैंड होल्ड्स।
- नियमित एलईडी प्रकाश व्यवस्था।
- पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन।
- 100% आधिक्य के साथ एचवीएसी सिस्टम।
- केंद्रीकृत कोच मॉनिटरिंग सिस्टम-एचवीएसी मॉनिटरिंग और नियंत्रण और सूचनाएँ/सतर्कता के लिए नियंत्रण केंद्र/कर्मचारियों के रखरखाव के लिए जीएसएम/जीपीआरएस से संप्रेषित करना।
- सीसीटीवी निगरानी कैमरे।
- दो डीटीसी कोचों में प्लेटफॉर्म कैमरे।



- कॉकपिट जैसा ड्राइवर केबिन।
- कैब रिकॉर्डिंग।
- सतर्कता नियंत्रण उपकरण और घटना रिकॉर्डर।
- चालक कैब में सिगनल एक्सचेंज लाइट्स।
- ऑन-बोर्ड सूचनात्मक जानकारी।
- जीपीएस-आधारित एलईडी डिस्प्ले और घोषणा प्रणाली।
- सभी कोचों में आग का पता लगाने की प्रणाली।
- प्रत्येक कोच में आपातकालीन लाइट्स।
- महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के लिए आग से सुरक्षा वाले केबल्स।
- विस्फोट-प्रूफ लिथियम आयन बैटरी।
- ओएचई विफलता की स्थिति में तीन घंटे का आपातकालीन बैकअप।
- आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट-आपात स्थिति में ड्राइवर से यात्री तक संवाद।
- केएवीएसीएच-ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली।



प्रधानमंत्री, भारत द्वारा श्रीलंका की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 6 अप्रैल, 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुरा में भारतीय सहायता से श्रीलंका में निर्मित दो रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ समारोह में भाग लिया। इस मौके पर 91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता से नवीनीकृत 128 कि.मी. लंबी माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद माहो से अनुराधापुरा तक 14.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता से बनाई जा रही एक उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली के निर्माण का शुभारंभ किया। भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित ये ऐतिहासिक रेलवे आधुनिकीकरण परियोजनाएँ श्रीलंका में उत्तर-दक्षिण रेल संपर्क को मजबूत करने में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। इससे देश भर में यात्री और माल यातायात दोनों की तेज और कुशल आवाजाही की सुविधा होगी।



भारतीय सहायता से श्रीलंका में निर्मित दो रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके

उत्कृष्टता का प्रकाशस्तंभ

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION
(A Government of India Enterprise)
Future on Track

आईआरएफसी वार्षिक परिणाम
वित्त वर्ष 2024-25

सशक्त वृद्धि, उत्कृष्ट परिणाम

गौरवान्वित करने वाले आंकड़े

- एक वित्त वर्ष के लिए राजस्व ₹27,156.41 करोड़
- कर चुकाने के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) ₹6,502 करोड़
- प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹4.98
- नेट वर्थ : ₹52,668 करोड़
- बुक वैल्यू : ₹40.30 प्रति शेयर
- वित्त वर्ष 2024-25 में लाभांश ₹3,005 करोड़
- उद्योग में उच्चतम जोखिम-भारित संपत्तियों के अनुपात में पूंजी (सीआरएआर) : 672.85%
- शून्य एनपीए बनाए रखा
- उद्योग में सबसे कम ओवरहेड : राजस्व का 0.1%
- Fortune India की 500 रेटिंग में सुधार : 91वीं स्थिति

कैबिनेट ने पांच प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

- ₹19,990 करोड़ का निवेश
- 1,360 कि.मी. नेटवर्क विस्तार
- 61 लाख से अधिक जनसंख्या को लाभ
- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 4 तथा 9 अप्रैल, 2025 को भारतीय रेल की पाँच बहुपटरी (मल्टी-ट्रैकिंग) परियोजनाओं को कुल ₹19,990 करोड़ लागत के साथ मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

ये परियोजनाएँ महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18 जिलों को कवर करते हुए भारतीय रेल नेटवर्क में 1,360 कि.मी. की अतिरिक्त लाइनें जोड़ेंगी और 61 लाख से अधिक लोगों को सीधे लाभ पहुँचाएंगी।

स्वीकृत परियोजनाएँ

संबलपुर-जरापड़ा (तीसरी और चौथी लाइन) ओडिशा
झारसुगुड़ा-सासोन (तीसरी और चौथी लाइन) ओडिशा

ये परियोजनाएँ कोयला और खनिज संपन्न क्षेत्रों की ढुलाई क्षमता बढ़ाएंगी तथा माल यातायात को तेज और कुशल बनाएंगी।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा (पांचवीं और छठी लाइन) छत्तीसगढ़

इस परियोजना से नया रायपुर स्मार्ट सिटी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। बलौदा बाजार जैसे क्षेत्रों में सीमेंट कारखानों और अन्य औद्योगिक इकाइयों की संभावनाएं बढ़ेंगी।

गोंदिया-बल्हारशाह (दोहरीकरण) महाराष्ट्र

यह परियोजना पूर्व-पश्चिम भारत को जोड़ने वाले एक प्रमुख मार्ग पर आधारित है, जिसमें 19 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। यह गढ़चिरौली और राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी।

तिरुपति-पाकाला-काटपाडी (दोहरीकरण) आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु

दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को मंजूर हुई इस 104 कि.मी. परियोजना से तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीकालहस्ती मंदिर, कनिपक्कम गणेश मंदिर और चंद्रगिरी किला जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों तक रेल पहुँच सुगम होगी। परियोजना 400 गांवों और 14 लाख आबादी को जोड़ेगी।



विवरण	परियोजनाएँ
नेटवर्क विस्तार	1,360 कि.मी.
कुल लागत	₹19,990 करोड़
राज्य	ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
जिलों की संख्या	18
गाँव लाभान्वित	3,750+
जनसंख्या लाभ	61.25 लाख
नए स्टेशन	19
अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता	9.277 करोड़ टन/वर्ष
तेल आयात में कमी	99 करोड़ लीटर
CO_2 उत्सर्जन में कमी	997 करोड़ किलोग्राम
पेड़ लगाने के बराबर प्रभाव	20 करोड़ पेड़

रणनीतिक और आर्थिक लाभ

इन परियोजनाओं से न केवल रेलवे की क्षमता और गति में वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, उद्योगों को कच्चा माल पहुँचाना, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना और आजीविका के नए अवसर पैदा करने में सहायक बनेंगी।

रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों पर भीड़भाड़ घटेगी

यात्री और माल परिवहन समय में कमी आएगी

खनिज, कोयला, उर्वरक, कृषि उत्पाद, इस्पात, सीमेंट आदि की ढुलाई में तेजी

स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्लस्टर और आकांक्षी जिलों को प्रोत्साहन



हरित भारत के लिए रेल की भूमिका

भारतीय रेल को दुनिया का सबसे हरित परिवहन माध्यम बनाने की दिशा में ये परियोजनाएँ मील का पत्थर सिद्ध होंगी :

CO_2 उत्सर्जन में कमी से भारत के नेट जीरो लक्ष्य को बल

तेल आयात में सालाना 990 मिलियन लीटर की बचत

200 मिलियन पेड़ों के बराबर कार्बन कटौती

ऊर्जा कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली का विस्तार



नया भारत, नई रेल

इन परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय रेल केवल पटरियाँ नहीं बिछा रही है, बल्कि वह नए भारत की नींव रख रही है- जहाँ हर गांव, हर जिला, हर उद्योग और हर नागरिक को जोड़ने का संकल्प लिया गया है।

'भारतीय रेल आज गति, गरिमा और गरीबी उन्मूलन का प्रतीक बनकर उभर रही है।'



अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश को मिली नई ट्रेन

अंबेडकर नगर-कोटा-नई दिल्ली एक्सप्रेस का शुभारंभ



कोटा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अंबेडकर नगर-कोटा-नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर दिनांक 13 अप्रैल, 2025 को डॉ. अंबेडकर नगर-कोटा-नई दिल्ली एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान नई ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में रेलवे की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की गति, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की प्रतीक हैं। यह केवल एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि विकास, संपर्क और सामाजिक समावेश की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। डॉ. अंबेडकर की जन्मस्थली तक यह सीधी रेल सेवा उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी। यह ट्रेन कोटा को दिल्ली, इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा, तीर्थाटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलवे के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। डॉ. अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी जन्मस्थली 'महू' से यह नई ट्रेन शुरू हो रही है। इससे महाकाल की नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित सिंहस्थ महाकुंभ के श्रद्धालुओं और इसके आस-पड़ोस के इलाकों में रहने वाले यात्रियों को यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा।

डॉ. यादव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के पर्यटन/दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देने एवं यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा सुगम आवागमन के उद्देश्य से रेलवे द्वारा नई ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री एवं रेलमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर डॉ. अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद उज्जैन अनिल फिरोजिया एवं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार उपस्थित रहीं तथा सांसद इंदौर शंकर लालवानी वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। बड़ी संख्या में स्थानीय जनसमूह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन तथा डॉ. अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ रेल अधिकारीगण भी मौजूद रहे।



अंबेडकर नगर-कोटा-नई दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भारतीय रेल मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में बेहतर सेवाएँ : रेल मंत्री

'बेहतर अवसंरचना, बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर रेलगाड़ियाँ' विषय पर दी विस्तृत जानकारी



मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को मुंबई में आयोजित 'बेहतर अवसंरचना, बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर रेलगाड़ियाँ' विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में रेलवे के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तनकारी प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर विशेष ध्यान देने के साथ आधुनिकीकरण, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बेहतर अवसंरचना

रेल मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अवसंरचना का विकास उपनगरीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए आधारशिला है। उन्होंने कहा कि लगभग ₹17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाएँ, 300 कि.मी. से अधिक नई लाइनों को कवर करती हैं, जो वर्तमान में तीव्र गति से चल रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य मौजूदा लाइनों पर भीड़भाड़ कम करना, सेवा आवृत्ति में सुधार करना और मुंबई के उपनगरीय यात्रियों की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करना है।

बेहतर प्रौद्योगिकी

रेल मंत्री ने कवच 5.0 के आगामी शुभारंभ की घोषणा की, जो उपनगरीय खंड के लिए तैयार की गई अत्याधुनिक सुरक्षा और सिग्नलिंग प्रणाली है। कवच 5.0 से अंतर-रेलगाड़ी हेडवे में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे अधिक रेलगाड़ियाँ सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सकेंगी।

बेहतर रेलगाड़ियाँ

रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़े सुधार के अंतर्गत, जल्द ही 238 नए वातानुकूलित उपनगरीय रेक शुरू किए जाएंगे। इन रेकों को मुंबई के यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनोखे ढंग से डिज़ाइन किया गया है, जो अधिक आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा का वादा करते हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह भी बताया कि मुंबई वन कार्ड जल्द ही शुरू किया जाएगा, जो उपनगरीय रेलगाड़ियों, मेट्रो रेल, मोनो-रेल, बेस्ट बसों आदि में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एमएमआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बदलने के लिए एकल और एकीकृत कार्ड है।

इस बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और रोलिंग स्टॉक की उन्नति से उपनगरीय सेवाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लाखों मुंबई वालों के लिए दैनिक परिवहन में परिवर्तनकारी सुधार होगा। रचनात्मक क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई में स्थापित किया जाएगा और यह भारतीय रचनात्मक उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी कदम होगा, जिससे यह विश्व स्तरीय अवसंरचना केन्द्र बन जाएगा।

महाराष्ट्र में महत्त्वपूर्ण रेल परियोजनाएँ

बातचीत के दौरान गोंदिया-बल्लारशाह रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक प्रमुख घोषणा की, जो ₹4,819 करोड़ के निवेश से 240 कि.मी. का महत्त्वपूर्ण गलियारा है। यह परियोजना विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ती है, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्री तथा माल ढुलाई में तेजी आएगी। यह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र के रेल संपर्क को भी मजबूत करेगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रमुख बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने की घोषणा दिनांक 7 अप्रैल, 2025 को की गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ₹18,658 करोड़ (लगभग) की कुल लागत वाली रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी।

रेल मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तनकारी परियोजना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यात्री और माल ढुलाई संपर्क बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वीकृत परियोजना में 240 कि.मी.

लंबे मौजूदा रेल ट्रैक के साथ व्यापक उन्नयन शामिल है, जिसमें 29 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 36 प्रमुख पुलों, 338 छोटे पुलों और 67 रोड अंडर-ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण शामिल है, ताकि परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

रेल मंत्री ने कहा, ''इस दोहरीकरण से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क में काफी सुधार होगा। क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में तेजी से विकास होगा।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह यात्रियों और रेल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर उद्योगों दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस उन्नयन से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य उल्लेखनीय रेल परियोजनाएँ

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में 132 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत देश भर में 1,300 स्टेशनों में से कई का काम पूरा होने वाला है, जबकि कई अन्य स्टेशनों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति की सूचना मिली है।

भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेलगाड़ी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बड़े पैमाने पर स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के साथ-साथ ये महत्त्वाकांक्षी उपक्रम महाराष्ट्र में परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं।

भारतीय रेल ने राज्य में अभूतपूर्व ₹1,73,804 करोड़ का निवेश किया है, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में महाराष्ट्र के रणनीतिक महत्त्व और इसके भविष्य के विकास पथ को रेखांकित करता है।

फडणवीस ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा महाराष्ट्र को रिकॉर्ड बजट आवंटन का महत्त्व और गोंदिया-बल्लारशाह स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण से क्षेत्र को लाभ हुआ। उन्होंने आईआरसीटीसी द्वारा जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज और यशस्वी मराठा पर्यटन रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के अन्य सांस्कृतिक और तीर्थ स्थलों के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और भव्य विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी द्वारा 10 दिनों की यात्रा के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई यात्रा की भी घोषणा की।

भारत रत्न डॉ. अंबेडकर की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि

रेल मंत्री एवं अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन



दिनांक 14 अप्रैल, 2025 को रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित बौद्ध धर्मगुरुओं ने रेल मंत्री को डॉ. अंबेडकर की तस्वीर भेंट स्वरूप दी।

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार सहित बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भी डॉ. अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ. अंबेडकर की स्मृति में इसी प्रकार के कार्यक्रम भारतीय रेल के समस्त कार्यालयों में आयोजित किए गए, जहाँ बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

छत्तीसगढ़ की नई धमनी बनेगी

खरसिया-परमालकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन, मिलेगा बंपर रोजगार : रेल मंत्री



रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व तोखन साहु, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरसिया-परमालकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन की जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व अन्य सांसद भी वर्चुअली जुड़े

केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेल प्रोजेक्ट के बारे में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 8 अप्रैल, 2025 को रेल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर ₹8,741 करोड़ की लागत आएगी और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया-परमालकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह ओडिशा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। इससे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चाँपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले जुड़ेंगे। इसके तहत 21 स्टेशन बनेंगे और 48 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही 349 माइनर ब्रिज बनेंगे। 14 फ्लाईओवर और 184 अंडरपास का निर्माण होगा। स्थानीय स्तर पर निवासियों को दिक्कत ना हो इसके लिए 5 रेल फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 615 कि.मी. लंबी पटरियां बिछेंगी, जिसमें 278 कि.मी. का रूट है। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग ₹2,500 करोड़ के डीजल की बचत होगी। रेल मंत्री ने कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता शबरी के प्रसंग से जुड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इस रेल नेटवर्क से संपर्क स्थापित होगा। बलौदा बाजार और खरसिया जैसे सीमेंट उत्पादन के बड़े इंडस्ट्रियल हब भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अब बायपास पद्धति को अपना रही है। इसके तहत मालगाड़ी को शहर के बाहर से निकालने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यात्री ट्रेनों को शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी। इस रेल लाइन के निर्माण के दौरान भी इस पर फोकस रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत डोकरा और कोसा सिल्क के उत्पादन वाले इलाके भी रेल लाइन के जरिए जुड़ेंगे। इसके चलते 2 करोड़ मैन डे जॉब क्रिएट होगा।

रेल मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ को लगभग 3 सौ करोड़ का रेलवे फंड मिलता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट अब 22 गुना बढ़कर लगभग 6,900 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही वर्ष 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसके तहत 1,125 कि.मी. नए ट्रैक बने हैं, जोकि दुबई के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से अधिक है। इसके तहत 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है और इन्हें पूरी तरह नया बनाया जा रहा है। इनमें से कई स्टेशनों के विकास का कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा।

रेल मंत्री ने कहा कि दल्लीराझरा से रावघाट नई लाइन पूरी होने वाली है। अब इसके आगे रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। वैसे ही गेवरा-पेन्ड्रा रोड नई लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन, झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, रायपुर-केन्द्री-धमतरी से अभनपुर-राजिम लाइन का गेज कन्वर्जन करके ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ चौथी लाइन, जगदलपुर से कोरापुट की डबलिंग, धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाइन, अनूपपुर से अंबिकापुर के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त फंड दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ा हजारों करोड़ का काम हो रहा है। नई परियोजना से छत्तीसगढ़ के छह सात जिले जुड़ते हैं, यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। स्टेशनों के विकास के लिए सरकार ने करोड़ों का फंड दिया है, इससे रेलवे और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी।

ऋषिकेश - कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना

सबसे लंबी रेल सुरंग - टनल नं. 8 का सफल ब्रेकथ्रू

हिमालयन कनेक्टिविटी की दिशा में भारतीय रेल का ऐतिहासिक कदम

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना के तहत 14.57 कि.मी. लंबी सौड-जनासू सुरंग का पहला ब्रेकथ्रू दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी की उपस्थिति में जनासू छोर पर संपन्न हुआ।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में 14.58 कि.मी. लंबी सुरंग संख्या 8 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बनने जा रही है। वर्तमान में सबसे लम्बी रेल सुरंग-उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के कटरा-बनिहाल सेक्शन पर खारी और सुंम्बड स्टेशनों के बीच 12.75 कि.मी. लम्बी टी-50 है।

इस उपलब्धि को 'शक्ति' नामक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा अंजाम दिया गया, जिसने मुख्य सुरंग की अंतिम चट्टान को भेदते हुए सुरंग को पार कर लिया। एक अन्य टीबीएम 'शिवा' के जरिए समानांतर सुरंग का कार्य जारी है और इसका ब्रेकथ्रू जुलाई 2025 तक होने की उम्मीद है। जैसे ही सुरंग की अंतिम परत टूटी, मौके पर मौजूद इंजीनियरों, अधिकारियों और मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने 'वंदे मातरम्' के जयघोष के साथ एक-दूसरे को गले लगाकर यह गौरवपूर्ण पल मनाया।

रेल मंत्री ने स्वयं स्थल का दौरा कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण टीम को उनके परिश्रम, संकल्प और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना की।

सौड-जनासू सुरंग इस महत्त्वाकांक्षी 125 कि.मी. लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों को जोड़कर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को नई दिशा देने का कार्य करेगी। इस रेल मार्ग का 83% से अधिक हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है, जिससे इसका निर्माण तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यह ब्रेकथ्रू न केवल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह सरकार की दूरस्थ क्षेत्रों तक मजबूत आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी पहुँचाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

अंतिम स्थल सर्वेक्षण (एफएलएस)

- भौगोलिक सीमाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम स्थल सर्वेक्षण (एफएलएस) में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया और सुरंगों, पुलों, रेलवे आदि के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों, प्रतिष्ठित संस्थानों तथा प्रख्यात विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ योजना के दौरान लिया गया।
- आईआईटी-रुड़की को सलाहाकर प्रमाणन का कार्य सौंपा गया, जिसकी अगुआई आईआईटी रुड़की के निदेशक ने की।
- कठिन भौगोलिक संरचना के कारण एफएलएस कार्य हेतु पहुँच की सीमाओं को पार करने के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया गया।



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यस्थल का दौरा कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण टीम को प्रोत्साहित किया

विश्व में नागरिक उपयोग के लिए उच्चतम रिजॉल्यूशन वाली स्टीरियो उपग्रह छवियाँ, जो 50 सेंटीमीटर रिजॉल्यूशन के साथ अमेरिकी वर्ल्ड व्यू-2 उपग्रह द्वारा ली गई थीं, उसका उपयोग उच्च सटीकता (2 मीटर) वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) को विकसित करने के लिए किया गया।

यह गूगल अर्थ की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। इसे आरईसीटी सर्वेक्षण में अंतिम रूप से निर्धारित एलाइनमेंट के दोनों ओर 2.5 कि.मी. के कॉरिडोर में लागू किया गया। आरईसीटी सर्वेक्षण, जिसमें किसी प्रस्तावित रेलवे लाइन या परियोजना के लिए प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, इंजीनियरिंग संभावनाएँ और यातायात से जुड़े आंकड़ों का संयुक्त अध्ययन किया जाता है।

हिमालयी दुर्गम भू-भाग में रेलवे लाइन का निर्माण जटिल भूविज्ञान के साथ कई प्रकार के जोखिमों, अनिश्चितताओं और तकनीकी चुनौतियों से भरा होता है।

इसी कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन निर्माण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की एक समिति को शामिल किया गया। इस समिति में रेल विशेषज्ञ एम. रविंद्र (पूर्व चेयरमैन, रेलवे बोर्ड), मेसर्स जियोकंसल्ट के अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ जे. गोलशर, ऑस्ट्रिया और अंतरराष्ट्रीय पुल विशेषज्ञ डॉ. वी. के. रैना -अंतरराष्ट्रीय पुल विशेषज्ञ रहे।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक की मुख्य विशेषताएँ

- 12 स्टेशन, 19 बड़े पुल, 38 छोटे पुल
- परियोजना की कुल लंबाई : 125.20 कि.मी.
- कुल लंबाई का 83% (104 कि.मी.) सुरंग
- 14.72% (18.4 कि.मी.) खुले तटबंध
- 2.21% (3.07 कि.मी.) महत्त्वपूर्ण पुलों की संख्या 16 है

परियोजना में कुल सुरंग की लंबाई 213.57 कि.मी. मुख्य सुरंग की कुल लंबाई 104 कि.मी. और सुरंग, 97.72 कि.मी. की 12 एस्केप सुरंग और 7.05 कि.मी. क्रॉस पैसेज)

सबसे लंबी

- सुरंग : 14.58 कि.मी.
- पुल की लंबाई : आधा कि.मी. (श्रीनगर पुल सं. 9)
- पुल की ऊँचाई 46.9 मीटर (गौचर पुल सं. 15)
- सबसे लंबा पुल : 125 मीटर देवप्रयाग पुल सं. 6

> *"संकल्प से सिद्धि तक!*
> *आज भारत की सबसे लंबी (14.5 कि.मी.) ट्रांसपोर्टेशन टनल का टनल बोरिंग मशीन द्वारा सफलतापूर्वक ब्रेकथ्रू हासिल किया गया है।"*
>
> अश्विनी वैष्णव
> रेल मंत्री

परियोजना की वर्तमान स्थिति

भूमि : कार्य शुरू करने से पहले भूमि अधिग्रहण का काम 100%

वन विभाग, सरकारी और निजी भूमि का विवरण

भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हे. में)	क्षेत्र (%)
वन विभाग	564.02	71.56
सरकारी	59.29	7.52
निजी	164.88	20.92
कुल	**788.20**	**100**

फास्ट ट्रैक कार्यों के लिए किए गए सहायक कार्य

पूरे परियोजना क्षेत्र के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1:5000 स्केल) और भू-भौतिकीय अध्ययन (भूकंपीय और प्रतिरोधक सर्वेक्षण)



भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग संख्या 8 की सफलता पर जश्न मनाया गया

पूरे हो चुके हैं। पूरी परियोजना के लिए कुल 164 बोर होल और 15.6 किमी रॉक ड्रिलिंग (600 मीटर गहराई तक) भू-तकनीकी जाँच (जीटीआई) पूरी कर ली गई है।

सभी प्रमुख पुलों के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी) और साइट-विशिष्ट सिस्मिक अध्ययन तथा एमएएसडब्ल्यू अध्ययन (आईआईटी रुड़की) से पूरे हो चुके हैं। विभिन्न कार्य स्थलों के लिए पहुँच मार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है।

मुख्य सुरंग के लिए एडिट्स टनल के कार्य हुए पूरे

प्रथम ब्लॉक सेक्शन

प्रथम ब्लॉक सेक्शन मौजूदा वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (पीके-1ए) के बीच आता है, जिसकी लंबाई 5.7 है, मार्च 2020 में चालू कर दिया गया था। इसके साथ ही ट्रेन रखरखाव की सुविधाएँ विकसित कर दी गई हैं।

सुरंग

- 16 सुरंगों को 10 पैकेजों में विभाजित किया गया है।
- सभी सुरंगों के सुरंग निर्माण कार्य एक साथ शुरू हुए।
- वर्तमान सुरंग निर्माण प्रगति (मुख्य सुरंग, एस्केप सुरंग, एडिट और क्रॉस पैसेज सहित) 213 कि.मी. के कुल विस्तार के मुकाबले 195 कि.मी. है।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमालयी भूगर्भीय भूभाग में सुरंग निर्माण में टीबीएम का पहला सफल प्रयोग किया गया है और भारतीय रेल में ऐसा पहला प्रयोग किया गया है।

रेलवे पुल

- कुल 19 प्रमुख पुल, 5 महत्त्वपूर्ण और 38 छोटे पुल। महत्त्वपूर्ण पुल गंगा नदी पर 1, चंद्रभागा नदी पर 1 और अलकनंदा नदी पर 3 हैं
- 19 प्रमुख पुलों में से 8 प्रमुख पुल पूरे हो चुके हैं। तीन महत्त्वपूर्ण पुल पूरे हो चुके हैं, एक चंद्रभागा नदी पर और दो अलकनंदा नदी पर।
- ऋषिकेश में एनएच/एसएचपर पर एक आरओबी और एक आरयूबी पूरा हो चुका है।
- गौचर, श्रीनगर और सिवाई में कार्य स्थलों तक पहुँच के लिए 3 प्रमुख सड़क पुल पूरे हो चुके हैं।
- शेष महत्त्वपूर्ण और प्रमुख पुलों 11 पर काम प्रगति की अग्रिम अवस्था में है।

कमीशनिंग लक्ष्य

- वीरभद्र-योग नगरी ऋषिकेश खंड दिनांक 20 मार्च, 2020 को चालू हुआ।
- परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। ट्रैक कार्य, इलेक्ट्रिकल, ओएचई और एसएंडटी कार्यों की योजना बनाई गई है और जल्द ही शुरू हो जाएगी।



दिनांक 16 अप्रैल, 2025 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं तथा विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

रेल राज्य मंत्री द्वारा आरओबी का निरीक्षण



रेल राज्य मंत्री वी. सोमण्णा ने दिनांक 5 अप्रैल, 2025 को बेंगलुरु में पदरायणपुरा और होसाहल्ली के बीच निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) संख्या 431 के कार्यों का निरीक्षण किया। यह नया आरओबी ₹12 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो पुराने आरओबी की जगह लेगा। पुराने आरोओबी का कोडल जीवन यानी निर्धारित सेवा काल पूरा हो चुका है। यह नया ब्रिज विजयनगर और मैसूर रोड के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। इसके बाद, सोमण्णा ने कृष्णदेवराय हॉल्ट स्टेशन और नायंडहल्लि स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने सांसदों के साथ की बैठक

दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे आर. एन. सिंह और सांसदों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में मदुरै मंडलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की गई और सांसदों को सूचित किया गया। बैठक में दक्षिण रेलवे की यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए निरंतर प्रतिबद्धता दर्शायी गई।



बैठक में सांसदों ने भाग लिया, जिनमें मावेलिक्करा सीट से कोडिक्कुन्निल सुरेश (लोकसभा), मावेलिक्करा, वाइको (राज्यसभा), मदुरै से एस. वेंकटेशन (लोकसभा), विरुधुनगर से मणिक्कम टैगोर (लोकसभा), तिरुनेलवेली से रॉबर्ट ब्रूस (लोकसभा), तेनकासी से डॉ. रानी श्रीकुमार (लोकसभा), थेनी से थंगा तमिलसेलवन (लोकसभा), तिरुचिरापल्ली से दुरई वाइको (लोकसभा), डिंडीगुली से आर. सचिदानंथम (लोकसभा), एम. मोहम्मद अब्दुल्ला (राज्यसभा) और आर. धर्मार (राज्यसभा) शामिल थे। सांसदों ने मदुरै मंडल के और अधिक विकास एवं सेवाओं में सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।



आपको यह **अंक कैसा लगा**
हमें जरूर बताएं

ई-मेल : editorbhartiyarailrb@gmail.com

पत्र लिखें ▶ **संपादक,** भारतीय रेल,
411, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001

स्वचालित व्हील मापन प्रणाली हेतु भारतीय रेल और डीएमआरसी के बीच समझौता



भारतीय रेल ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली (एडब्ल्यूपीएमएस) की खरीद और स्थापना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके रोलिंग स्टॉक रखरखाव में स्वचालन और दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह समझौता दिनांक 4 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में औपचारिक रूप किया गया।

इस अवसर पर बी.एम. अग्रवाल, सदस्य (ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक) एस.के. पंकज, अतिरिक्त सदस्य (उत्पादन इकाइयाँ) आशीष शर्मा, अतिरिक्त सदस्य (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) परमीत गर्ग, निदेशक (व्यवसाय विकास), डीएमआरसी उपस्थित थे।

एडब्ल्यूपीएमएस एक उन्नत प्रणाली है जो ट्रेन के पहियों की प्रोफाइल को स्वचालित और गैर-संपर्क तरीके से मापन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे पहियों की ज्यामिति और घिसाव का वास्तविक समय पर आकलन सुनिश्चित होता है। लेजर स्कैनर और हाई-स्पीड कैमरों का उपयोग करके यह प्रणाली बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सटीक और त्वरित माप प्रदान करती है। विचलन की किसी भी स्थिति में, स्वचालित अलर्ट प्रणाली समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, जिससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता दोनों में वृद्धि होगी।

इस साझेदारी के तहत, डीएमआरसी भारतीय रेल के लिए चार एडब्ल्यूपीएमएस इकाइयों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग की जिम्मेदारी संभालेगी।

यह सहयोग रेलवे रखरखाव प्रथाओं के आधुनिकीकरण में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके भारतीय रेल अपने रोलिंग स्टॉक प्रबंधन को बेहतर बना रहा है, रखरखाव समय को कम कर रहा है और समग्र सेवा दक्षता में सुधार कर रहा है। यह साझेदारी भारतीय रेल और डीएमआरसी के बीच प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और कौशल विकास को भी बढ़ावा देती है, जो नवाचार, सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।■

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोए

रेल मंत्रालय द्वारा विगत 69 वर्षों
से भी अधिक समय से प्रकाशित मासिक पत्रिकाओं

अब ई-पत्रिका भी उपलब्ध

की सदस्यता अब
ऑनलाइन
भी उपलब्ध



भारतीय रेल
(हिन्दी)

क्यू आर कोड स्कैन करें
विजिट करें



Indian Railways
(English)

www.irctctourism.com/IRBRmag/#/home/hn

भारतीय रेल ने प्राप्त किया ₹2.56 लाख करोड़ का राजस्व

वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध लाभ रहा ₹3,260 करोड़

गति और विस्तार

- **विद्युतीकरण, कार्यबल अनुकूलन और परिचालन क्षमता के माध्यम से लागत प्रबंधन को मजबूती दी गई, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 में डीजल पर ₹4,700 करोड़ की बचत हुई।**
- **रेलवे हॉग ट्रेनों, विद्युतीकरण, एलईडी उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों के साथ हरित और सतत पहलों में अग्रणी रहा।**
- **रेल नेटवर्क : गति क्षमता 110 कि.मी. प्रति घंटे के साथ 80,000 कि.मी. तक विस्तार, वर्ष 2014 के बाद से 130 कि.मी. प्रति घंटे के लिए 23,000 कि.मी. रूट को उन्नत किया गया।**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारतीय रेल की आय ₹2,56,093 करोड़ थी और राजस्व व्यय ₹2,52,834 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध राजस्व ₹3,260 करोड़ हो गया है। प्रमुख व्यय कर्मचारियों की लागत, पेंशन, ऊर्जा खपत आदि पर किया जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल ने दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है- राजस्व में वृद्धि करना और परिचालन व्यय में दक्षता लाना।

कई माल भाड़ा राजस्व पहलों के कार्यान्वयन के कारण, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रेलवे द्वारा किया गया माल परिवहन 29% की वृद्धि के साथ 1,591 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,233 मिलियन टन था, जिससे यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे प्रणाली बन जाएगा। माल परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं-

- निजी क्षेत्र को 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) की नीति के तहत आधुनिक रेल माल ढुलाई बढ़ाना टर्मिनलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और रेलवे स्वामित्त्व वाले माल शेड में अवसंरचना को बढ़ाना/ उन्नयन करना।
- वैगनों में निवेश को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना, जिसमें शामिल हैं- माल केंद्रित विशेष वैगन, जैसे सीमेंट, तेल, स्टील, फ्लाई-ऐश, ऑटोमोबाइल आदि।
- कार्गो एकत्रीकरण को सुविधाजनक बनाना और इस तरह, 'कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद' और 'संयुक्त पार्सल उत्पाद-त्वरित कार्गो सेवाओं' की नीति सहित योजनाओं द्वारा माल बास्केट का विस्तार करना।



- सड़क की तुलना में रेल परिवहन को प्रतिस्पर्धी बनाकर रेल हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई टैरिफ से संबंधित उपायों को लागू करना। इनमें 90 कि.मी. तक यातायात के लिए शॉर्ट लीड रियायत, खाली प्रवाह दिशा में लोड किए गए ट्रैफिक के लिए उदार स्वचालित माल ढुलाई की योजना, खुली और फ्लैट वैगन में बोरियों को लोड करने पर छूट, फ्लाई ऐश/बेड ऐश ट्रैफिक के लिए फ्रेट में छूट, कंटेनर ट्रेन के लिए मिनी रेक का संचालन, थोक सीमेंट (बिना बोरियों के) के लिए विशेष हॉलेज की दर का निर्धारण करना किया जाता है, जब परिवहन सामान्य कंटेनर में किया जा रहा हो।

भारतीय रेल ने गैर-किराया राजस्व को बढ़ाने के लिए कई पहल की है, जैसे विज्ञापन आय बढ़ाने के उपाय, अभिनव राजस्व-वृद्धि विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए निनफ्रिस (गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए नए और अभिनव विचार और अवधारणा योजना) को लागू करना। निनफ्रिस अनुबंध के कुछ उदाहरण हैं- नर्सिंग पॉड्स, सामान रैपिंग और स्वच्छता, डिजिटल अमानती-सामानघर, डिस्पोजल लिनन कियॉस्क, इमिटेशन ज्वेलरी कियॉस्क, खादी विक्रय कियॉस्क, हस्तकला कियॉस्क, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए कियॉस्क, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा, ऑक्सीजन पार्लर आदि। पट्टे पर दिए गए पार्सल स्थल, पार्किंग स्थल, एटीएम जैसी परिसंपत्तियों की नीलामी में तेजी लाने के लिए ई-नीलामी नीति लागू की गई है। ई-नीलामी मॉड्यूल के लाभों में शामिल हैं- प्रत्येक परिसंपत्ति की वास्तविक आय क्षमता का पता लगाना, निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय में कमी लाना और इस कारण होने वाली राजस्व हानि को रोकना, किसी ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने में विफलता की स्थिति में शीघ्रता से अनुबंध को पुनः प्रदान करना आदि।

भारतीय रेल ने यात्री खंड से आय में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे विशेष ट्रेनों को चलाना, ऑन-बोर्ड क्षमता में वृद्धि और उपयुक्त किराए के साथ उच्च सुविधाओं से युक्त नई ट्रेनों की शुरुआत।

इसी तरह, इष्टतम व्यय सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में नियमित रूप से विभिन्न उपायों को लागू किया जा रहा है। रेलवे के व्यय प्रबंधन उपायों में शामिल हैं- जनशक्ति प्रबंधन, रेलवे पटरियों का विद्युतीकरण आदि। रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण जैसे उपायों से वित्त वर्ष 2023-24 में डीजल ट्रैक्शन के तहत ₹4,700 करोड़ से अधिक की बचत हुई।

स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है तथा स्टेशनों और ट्रेनों में सफाई बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं- स्टेशनों और ट्रेनों में एकीकृत हाउसकीपिंग अनुबंध, मशीनीकृत सफाई, यात्री कोचों में जैव-टॉयलेट्स, लंबी दूरी की ट्रेनों में बोर्ड



हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस) योजना पर, मार्ग में चिह्नित ट्रेनों के लिए नामित स्टेशनों पर स्वच्छ ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) योजना, जैव अपशिष्ट और गैर-जैव अपशिष्ट के लिए कूड़ेदान आदि।

पर्यावरण-अनुकूल हेतु उठाए गए विभिन्न कदम

- शोर, वायु प्रदूषण और डीजल की खपत को कम करने के लिए एंड ऑन जेनरेशन (ईओजी) ट्रेनों को हेड ऑन जेनरेशन (एचओजी) में बदलना।
- पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों (डीएफसी) का निर्माण।
- अपनी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद।
- बिजली की खपत में कमी के लिए स्टेशनों, सेवा भवन, आवासीय क्वार्टर और कोच सहित सभी रेलवे प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश का प्रावधान।



- स्टार श्रेणी के उपकरणों का उपयोग।
- 98% रेलवे पटरियों को विद्युतीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप डीजल की खपत में कमी आई है।
- ट्रेन चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग।
- रेलवे प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण-पत्र।
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन।

यात्रियों की सुरक्षा और आराम को बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक में सुधार/उन्नतीकरण रेलवे की निरंतर और जारी प्रक्रिया है। इन पहलों में वर्ष 1960 के दशक के पारंपरिक आईसीएफ कोचों की तुलना में 160 कि.मी. प्रति घंटे की परिचालन गति, बेहतर राइडिंग इंडेक्स, बेहतर सौंदर्य और हल्के वजन की डिज़ाइन, एंटी-टेलिस्कोपिक और एंटी क्लाइम्बिंग विशेषताएँ, सेंटर बफर कपलर, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम जैसी सुरक्षा विशेषताएँ शामिल हैं।

यात्रियों को तेज सेवा और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयास में, भारतीय रेल वंदे भारत ट्रेनें और नमो रैपिड रेल सेवा शुरू कर रहा है, जिसमें आधुनिक कोच, बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ और अच्छी सुविधाएँ हैं। वर्तमान में, भारतीय रेल नेटवर्क पर 136 वंदे भारत सेवाएँ और 2 नमो रैपिड रेल सेवाएँ चल रही हैं।

भारतीय रेल ने आधुनिक, नॉन-एसी अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की हैं। इन ट्रेनों में झटके रहित यात्रा के लिए सेमी-परमानेंट कपलर, क्षैतिज स्लाइडिंग विंडो, वंदे भारत स्लीपर की तर्ज पर बेहतर परिदृश्य व आराम के साथ बर्थ की बेहतर सुंदरता, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट, मोड़े जाने लायक स्नैक टेबल और बोतल रखने की जगह, मोबाइल होल्डर आदि जैसी उन्नत सुविधाएँ हैं। इन ट्रेनों में 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं। वर्तमान में, 4 अमृत भारत सेवाएँ चल रही हैं।

रेलवे ट्रैक को उन्नत करने के लिए किए गए उपाय-

- 60 किग्रा, 90 अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) नॉर्मल/वाइड बेस स्लीपर के साथ आधुनिक इलास्टिक फास्टनिंग वाले आधुनिक ट्रैक घटकों का उपयोग करना।
- पीएससी स्लीपरों पर मोटी वेब स्विच और वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के साथ पंखे के आकार का टर्नआउट बिछाना।
- प्राथमिक ट्रैक नवीनीकरण करते समय गर्डर पुलों पर स्टील चौनल/एच-बीम स्लीपर प्रदान करना।
- वेल्ड-जोड़ों को न्यूनतम करने के लिए रेल नवीनीकरण के तहत 130 मीटर/260 मीटर लंबे रेल पैनल का उपयोग करना।
- मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट द्वारा फील्ड-वेल्डिंग और चरणबद्ध सरणी प्रौद्योगिकी द्वारा रेल/वेल्ड की उन्नत यूएसएफडी परीक्षण तकनीक।



- ट्रैक रिलेइंग ट्रेनों, पॉइंट्स और क्रॉसिंग चेंजिंग मशीनों, ट्रैक बिछाने के उपकरण आदि का उपयोग करके ट्रैक नवीनीकरण/प्रतिस्थापन में यांत्रिकीकरण।
- सर्वोत्तम रखरखाव आवश्यकताओं के अनुमान के लिए व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन हेतु एकीकृत ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (आईटीएमएस) और ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएमएस) की तैनाती।
- ट्रैक रखरखाव के लिए उन्नत आधुनिक मशीनों का उपयोग, जैसे उच्च आउटपुट टैम्पर, उच्च आउटपुट बैलस्ट क्लीनिंग मशीन और रेल ग्राइंडिंग मशीन आदि।
- रेल/वेल्ड के परीक्षण के लिए स्व-चालित अल्ट्रासोनिक रेल परीक्षण कार (एसपीयूआरटी) और रेल सह सड़क वाहन (आरसीआरवी) आधारित यूएसएफडी प्रणाली को अपनाना।
- बेहतर रखरखाव, इनपुट को सक्षम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ट्रैक निरीक्षण रिकॉर्ड के एकीकरण और डेटा विश्लेषण के लिए वेब सक्षम ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का उपयोग करना।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, 110 कि.मी. प्रति घंटे की गति क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह वर्तमान में लगभग 80,000 कि.मी. हो गई है, जो वर्ष 2014 में केवल लगभग 31,000 कि.मी. थी। इसके अतिरिक्त, 130 कि.मी. प्रति घंटे की गति क्षमता के लिए वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) तक लगभग 23,000 कि.मी. ट्रैक का उन्नयन और सुधार किया गया है।

भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को सस्ती सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर ₹56,993 करोड़ की सब्सिडी दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत ₹100 है, तो टिकट की कीमत केवल ₹54 है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इस सब्सिडी राशि के अलावा भी कई श्रेणियों के लिए रियायतें जारी हैं, जैसे दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियां, मरीजों की 11 श्रेणियां और छात्रों की 8 श्रेणियां।

भारतीय रेल ने घरेलू कंटेनर लोडिंग में पाई बड़ी सफलता

माल लदान में 19.72% की वृद्धि, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.68% अधिक



भारतीय रेल उद्योग और ऊर्जा-बिजली संयंत्रों के लिए कोयला, विनिर्माण और निर्माण के लिए लौह अयस्क और तैयार इस्पात, सीमेंट, राष्ट्रीय वितरण के लिए खाद्यान्न, कृषि के लिए उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए आवश्यक थोक वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण साधन है। लंबी दूरी तक बल्क में माल ढुलाई के लिए सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन अधिक किफायती और उपयोगी है। इससे व्यवसायों के लिए समग्र रसद लागत (लॉजिस्टिक कॉस्ट) को कम करने में मदद मिलती है। इससे भारतीय सामान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। इसके अलावा यह रेलवे खदानों, कारखानों, कृषि क्षेत्रों और बंदरगाहों को देश भर के बाजारों से जोड़ता है, जिससे निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेल ने लगभग 1,617.38 मिलियन टन प्रारंभिक माल लदान हासिल किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1,590.68 मिलियन टन लदान हासिल किया। इस प्रकार लोडिंग में 26.70 मिलियन टन (1.68%) की वृद्धि दर्ज की गई।

घरेलू कोयले की लोडिंग में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि घरेलू कंटेनर की लोडिंग में 19.72% की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक की लोडिंग में 1.25% की वृद्धि दर्ज की गई। पीओएल लोडिंग में 0.61% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू कंटेनर में बोरियां, हॉट रोल्ड कॉइल, सिरेमिक टाइलें, वॉल केयर पुट्टी और चावल पांच प्रमुख वस्तुएं हैं।

क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्राप्त लोडिंग के संदर्भ में, पूर्व रेलवे ने 16.11% की, जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7.28% की वृद्धि हासिल की। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने 4.21% उत्तर रेलवे ने 3.89%, पूर्व मध्य रेलवे ने 2.82%, दक्षिण मध्य रेलवे ने 2.14% की वृद्धि हासिल की। पूर्वी तट रेलवे ने 1.19% की वृद्धि हासिल की। दक्षिण रेलवे ने 0.80% की वृद्धि हासिल की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 0.36% की वृद्धि हासिल की। भारतीय रेल द्वारा कोयले की अधिक लोडिंग के कारण भारत में बिजली घरों में स्टॉक 57 मिलियन टन तक पहुँच गया।

किसान रेल सेवाओं का परिचालन

जल्दी खराब होने वाली 7.9 लाख टन वस्तुओं की हुई ढुलाई

किसान रेल उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की उचित समय पर ढुलाई करती है और इन वस्तुओं की कमी वाले क्षेत्रों में पहुँचाने में सक्षम बनाती है।

दिनांक 7 अगस्त, 2020 को किसान रेल सेवा के लॉन्च करने के बाद से, रेलवे ने लगभग 7.9 लाख टन जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन करते हुए लगभग 2,364 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है। इनमें से, 65 सेवाएँ गुजरात से देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित की गई हैं, जिनके जरिए 18,250 टन फलों और सब्जियों का परिवहन हुआ है।

सब्जियों, फलों और जल्दी खराब होने वाली अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए संभावित सर्किट की पहचान कृषि और किसान



कल्याण तथा कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और एजेंसियों, मंडियों आदि के साथ परामर्श से की जाती है और परिचालन संभावना को ध्यान में रखते हुए मांगों के आधार पर योजना बनाई जाती है।

भारतीय रेल ने की पारदर्शी राजस्व निगरानी की डिजिटल व्यवस्था

नियमित कार्यबल मूल्यांकन से कुशल जनशक्ति उपयोग सुनिश्चित हुआ



भारतीय रेल में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्राप्त राजस्व की निरंतर निगरानी के लिए एक व्यापक व्यवस्था है। यात्री आय और लोगों के आगमन के आधार पर, रेलवे स्टेशनों को गैर-उपनगरीय श्रेणी (एनएसजी1-6), उपनगरीय श्रेणी (एसजी1-3) और हाल्ट श्रेणी (एचजी1-3) स्टेशनों में वर्गीकृत किया गया है।

स्टेशन पर राजस्व के स्रोतों में शामिल हैं

- **यात्री आय :** आरक्षित यात्री आय (यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से) और अनारक्षित यात्री आय (अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से)।
- **माल ढुलाई से आय :** माल का परिवहन, लदान में देरी से होने वाली आय, माल रखरखाव के लिए रेलवे की सुविधा के उपयोग से होने वाली आय आदि।
- **कोच से अन्य आय :** पार्सल, सामान, प्लेटफॉर्म टिकट, पोस्टल ढुलाई शुल्क, क्लॉक रूम शुल्क, पार्सल में देरी से होने वाली आय, पार्सल रखरखाव के लिए रेलवे की सुविधा के उपयोग से होने वाली आय आदि।
- **विविध आय :** किराए से राजस्व, पट्टे पर पार्किंग स्थल, खानपान प्राप्तियाँ, भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से राजस्व, कोच और स्टेशनों पर विज्ञापन आदि।
- संबंधित प्रभाग के वाणिज्यिक निरीक्षकों, खातों के यात्रा निरीक्षकों आदि जैसे नामित अधिकारी राजस्व की निगरानी करते हैं। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न राजस्व की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी स्तरों यानी स्टेशन, खंड और मंडल मुख्यालय पर की जाती है।

वर्तमान राजस्व प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, निम्न डिजिटल अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें सीआरआईएस के डोमेन विशेषज्ञों (रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र) द्वारा विकसित किया गया है-

- यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस)
- टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस)
- पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)
- माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस)
- यातायात खाता प्रबंधन प्रणाली (टीएएमएस)
- ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
- ई-भुगतान प्रणाली
- ई-बैलेंस शीट
- भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस)

मानव संसाधन भारतीय रेल की बहुत महत्त्वपूर्ण संपत्ति है। यह जरूरी है कि इसका उपयोग प्रभावी रूप से कुशलतापूर्वक और तर्कसंगत रूप से किया जाए। जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए जनशक्ति की निरंतर समीक्षा जरूरी है, ताकि कार्यभार की स्थिति में बदलाव किया जा सके, नई प्रौद्योगिकियों, कार्य प्रणालियों की शुरुआत की जा सके और नई परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।

भारतीय रेल प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार का आकलन करने के लिए नियमित रूप से समय-समय पर मानकों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, कर्मचारियों के प्रावधान की समीक्षा करने तथा विभिन्न विभागों की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक जनशक्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य अध्ययन और मानकीकरण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार को रोजगार नियमों (एचओईआर) के घंटों के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो वैधानिक है। एचओईआर के अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण भी समय-समय पर नौकरी विश्लेषण के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह अभ्यास भारतीय रेल को नए संगठनों और परिसंपत्तियों के लिए जनशक्ति को तैनात करने में तथा अपने मौजूदा मानव संसाधनों का उपयोग सबसे कुशल और उत्पादक तरीके से करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय रेल द्वारा 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों पर 209 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित

भारतीय रेल नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरणीय स्थायित्व को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक वित्त बचत प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों के अनुरूप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना एक सतत प्रक्रिया है।

भारतीय रेल ने चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक, आरटीसी) बिजली के लिए विभिन्न विद्युत खरीद मोड के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की उत्तरोत्तर खरीद के लिए योजना बनाई है, जो नवीकरणीय विद्युत के लिए हाइब्रिड समाधान है, जिसमें सौर और हवा ऊर्जा शामिल हैं। सौर संयंत्रों की स्थापना का अधिकांश काम डेवलपर मोड के तहत बिजली खरीद समझौते के माध्यम से रेलवे द्वारा किया जाता है।

सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन के दौरान, रेलवे द्वारा नियामक बाधाओं, शक्ति निकासी और कनेक्टिविटी जैसी कई चुनौतियों का सामना किया गया था। इन मुद्दों से निपटने के लिए, राज्य सरकारों और पारेषण उपयोगिता कंपनियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की गयी।



अब तक, देश भर में 2249 रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों पर लगभग 209 मेगावाट के सौर संयंत्र मौजूद हैं। राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	राज्य	रेलवे स्टेशन पर सौर संयंत्र प्रदान किए गए (संख्या)		
		2014-15 से 2019-20	2020-21 फरवरी, 2025	संचयी फरवरी, 2025 तक
1	राजस्थान	73	200	275
2	महाराष्ट्र	43	213	270
3	पश्चिम बंगाल	12	222	237
4	उत्तर प्रदेश	78	93	204
5	आंध्र प्रदेश	33	126	198
6	कर्नाटक	86	60	146
7	मध्य प्रदेश	49	74	134
8	ओडिशा	30	103	133
9	गुजरात	11	96	112
10	तेलंगाना	35	60	95
11	बिहार	25	42	81
12	असम	27	48	78
13	तमिलनाडु	42	31	73
14	झारखंड	10	35	47
15	हरियाणा	9	23	36
16	पंजाब	19	11	30
17	उत्तराखंड	1	17	18
18	हिमाचल प्रदेश	1	16	17
19	त्रिपुरा	15	1	16
20	छत्तीसगढ	10	5	16
21	केरल	12	1	13
22	दिल्ली	4	3	8
23	जम्मू-कश्मीर	2	4	6
24	नगालैंड	0	2	2
25	मेघालय	0	1	1
26	मणिपुर	0	1	1
27	चंडीगढ़	0	1	1
28	पुदुचेरी	1	0	1
	कुल	**628**	**1,489**	**2,249**

लोकोमोटिव उत्पादन में अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकला भारत

वित्त वर्ष 2024-25 में 1,681 लोकोमोटिव का किया रिकॉर्ड उत्पादन

- **'मेक इन इंडिया' से विकास, पिछले 10 वर्षों में लोकोमोटिव उत्पादन बढ़कर 9,168 हुआ, वार्षिक औसत दोगुना यानी 917 तक पहुँचा**
- **उत्पादन में 19 % की वृद्धि, वित्त वर्ष 2023-24 में 1,472 हुआ था उत्पादन**



भारत रेल लोकोमोटिव निर्माण में वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। इसने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,681 लोकोमोटिव का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पार कर गई है, जो वैश्विक रेलवे के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभुत्व की पुष्टि करता है।

भारतीय रेल की लोकोमोटिव निर्माण इकाइयों ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 1,681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादित 1,472 लोकोमोटिव की तुलना में 209 लोकोमोटिव या 19% की वृद्धि दर्शाता है। यह रिकॉर्ड-तोड़ उत्पादन देश में लोकोमोटिव निर्माण के लिए अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है, जो रेलवे के बुनियादी ढाँचे और क्षमता को बढ़ाने में सभी इकाइयों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है।

लोकोमोटिव उत्पादन में निरंतर वृद्धि 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करने हेतु लिए गए रणनीतिक निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच भारत ने कुल 4,695 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जबकि राष्ट्रीय वार्षिक औसत 470 रहा। इसके विपरीत, वर्ष 2014 से 2024 तक लोकोमोटिव निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 9,168 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ, जिससे उत्पादन का वार्षिक औसत लगभग 917 हो गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने अपनी विनिर्माण इकाइयों में 1,681 इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया।

यूनिट	उत्पादन
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	700
बनारस लोकोमोटिव वर्क्स	477
पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स	304
मधेपुरा इकाई	100
मढ़ौरा इकाई	100
कुल उत्पादन	**1,681**

देश में उत्पादित अधिकांश लोकोमोटिव मालगाड़ियों के लिए हैं।

लोकोमोटिव	उत्पादन
WAG-9/9H लोकोमोटिव	1,047
WAG-9HH लोकोमोटिव	7
WAG-9 ट्विन लोकोमोटिव	148
WAP-5 लोकोमोटिव	2
WAP-7 लोकोमोटिव	272
NRC लोकोमोटिव	5
WAG-12B लोकोमोटिव	100
WDG 4G/6G लोकोमोटिव	100

वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने बनाए 7,134 नए कोच

आम जन के लिए भारतीय रेल ने पिछले एक दशक में औसतन बनाए 5,481 कोच, जो है अब तक का नया रिकॉर्ड

भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 7,134 कोच बनाकर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले वर्ष के 6,541 कोचों के उत्पादन से 9% की वृद्धि को दर्शाता है, इसमें नॉन-एसी कोचों पर विशेष जोर देते हुए 4,601 कोचों का उत्पादन किया गया है, जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा करता है। यह वृद्धि, बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाती है।

भारतीय रेल की देश में तीन कोच निर्माण इकाइयाँ हैं- चेन्नई, तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), कपूरथला, पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) और रायबरेली, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) चेन्नई स्थित भारतीय रेल की प्रमुख यात्री कोच उत्पादक इकाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने पिछले उत्पादन रिकॉर्ड को पार कर लिया, क्योंकि इसने 3,007 कोच तैयार किए।

कोच निर्माण इकाई	स्थान	उत्पादित कोचों की संख्या (2023-24)	उत्पादित कोचों की संख्या (2024-25)	उत्पादन में वृद्धि
इंटीग्रल कोच (आईसीएफ)	चेन्नई, तमिलनाडु	2,829	3,007	+178
रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ)	कपूरथला, पंजाब	1,901	2,102	+201
मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ)	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1,684	2,025	+34

घरेलू विनिर्माण में वृद्धि

भारत में कोच उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच, भारतीय रेल ने प्रति वर्ष औसतन 3,300 से कम कोच का निर्माण किया। हालांकि, वर्ष 2014 से 2024 के दौरान, उत्पादन में 54,809 कोचों के उत्पादन के साथ प्रति वर्ष औसतन 5,481 कोचों के उत्पादन के साथ बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, जो रेलवे विनिर्माण में बेहतर परिवहन-संपर्क सुविधा पर जोर और आत्मनिर्भरता के अनुरूप है। यह विस्तार घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम



करने और रेलवे डिज़ाइन में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

यात्री अनुभव और परिवहन-संपर्क सुविधा में सुधार

रिकॉर्ड कोच उत्पादन सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' विजन के अनुरूप है, जो घरेलू विनिर्माण को सक्षम करने के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ सुनिश्चित करता है। अधिक कोच पेश किए जाने से, यात्री बेहतर सुविधाओं, बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई क्षमता की उम्मीद कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह उपलब्धि 'मेक इन इंडिया पहल' को मजबूत करती है, जिससे रेल-निर्माण में भारत की प्रमुख भूमिका को बल मिलता है। आधुनिक, ऊर्जा-कुशल और यात्री-अनुकूल कोचों पर ध्यान केंद्रित करके, भारतीय रेल एक अधिक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार परिवहन नेटवर्क बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

रेलवे विद्युतीकरण, हाई-स्पीड कॉरिडोर और उन्नत यात्री सेवाओं के चल रहे प्रयासों के साथ, बढ़ा हुआ कोच उत्पादन भारत की रेल परिवहन प्रणाली के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे लाखों यात्रियों के लिए अधिक दक्षता, आराम और पहुँच सुनिश्चित होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में रेल वैगन का रिकॉर्ड उत्पादन

- **पिछले तीन वर्षों में कुल वैगन उत्पादन 1,02,369 इकाई तक पहुँचा, जिससे रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि हुई**
- **कुल 41,929 इकाई उत्पादन के साथ वार्षिक वृद्धि 11%**
- **वर्ष 2004-14 के औसत उत्पादन में तीन गुना वृद्धि**

भारतीय रेल ने वैगन उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 41,929 वैगनों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादित रेल वैगनों की संख्या 37,650 से अधिक है। यह वित्त वर्ष 2004-2014 के बीच उत्पादित 13,262 वैगनों के वार्षिक औसत की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति है, जो विनिर्माण क्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

इस वृद्धि से माल ढुलाई की अड़चनें कम होने और रेल माल ढुलाई में वृद्धि होने की उम्मीद है। ये आंकड़े वार्षिक वैगन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, जो न केवल घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने बल्कि माल ढुलाई में सुधार करने के सरकार के दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करते है। इस वृद्धि से सुविधा बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत आर्थिक रूप से सशक्त बनने के अपने लक्ष्य की ओर सशक्त होगा।

अवधि	उत्पादन
2004-2014 (औसत)	13,262
2014-2024 (औसत)	15,875
2022-2023	22,790
2023-2024	37,650
2024-2025	41,929
पिछले तीन वर्षों में कुल उत्पादन	**1,02,369**

आर्थिक वृद्धि

वैगन उत्पादन में इस बढ़ोतरी का आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में जबर्दस्त प्रभाव होने की उम्मीद है। अधिक वैगन उपलब्ध होने से, परिवहन की अड़चनें काफी हद तक कम हो जाएंगी, जिससे माल की तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी और कोयला,



सीमेंट और स्टील जैसे थोक परिवहन पर निर्भर उद्योगों के लिए बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी। सड़क माल ढुलाई पर निर्भरता कम कर, यह बदलाव ईंधन की खपत और उत्सर्जन को भी कम करेगा, जो स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई में बेहतर दक्षता परिवहन लागत को कम करने में मदद करेगी, जिससे अंततः मुद्रास्फीति के दबाव को कम करके व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाना

भारतीय रेल अपनी माल ढुलाई क्षमता का विस्तार जारी रखते हुए भारत के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह वृद्धि घरेलू विनिर्माण और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।



आगरतला, त्रिपुरा स्थित निश्चिंतपुर टर्मिनल ने तेतेलिया, गुवाहाटी से भेजे गए पहले माल लदान-बीसीएन वैगन को प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही यह आगरतला सिटी की दूसरी माल ढुलाई टर्मिनल बन गई है।

क्या आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है ?

आरपीएफ आपका मददगार - मोबाइल फोन को ब्लॉक कर उसकी तलाश करेगी

रेलवे और दूरसंचार विभाग की साझीदारी में शुरू हुई निगरानी, आपको मिलेगा आपका मोबाइल फोन

खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन यात्रियों को वापस करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दूरसंचार विभाग के केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल से सफलतापूर्वक जुड़ गया है। यह पहल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) में एक पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद की गई है। पूरे भारत में भारतीय रेल में इस कार्यक्रम के लागू होने से लाखों रेल यात्रियों को लाभ होगा।

दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को आयोजित सीईआईआर पोर्टल के उद्घाटन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने आरपीएफ क्षेत्रीय इकाइयों की सभा को संबोधित किया। सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल ने इस मौके पर मुख्य भाषण दिया। महानिदेशक ने कहा, "सीईआईआर पोर्टल के संचालन के लिए दूरसंचार विभाग के साथ आरपीएफ का सहयोग रेलवे सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके, हमारा उद्देश्य यात्रियों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस पाने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी तंत्र प्रदान करना है। यह पहल कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करती है और रेल यात्रियों के बीच अधिक विश्वास को बढ़ावा देती है। हम यात्रियों की संपत्ति की सुरक्षा और रेलवे नेटवर्क में सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

दूरसंचार विभाग का सीईआईआर पोर्टल एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल टूल है, जिसे खोए या चोरी हुए उपकरणों को ब्लॉक, ट्रैक और प्रबंधित करके मोबाइल फोन को वापस पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, आरपीएफ अब खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके आईएमईआई नंबर को ब्लॉक करके अनुपयोगी बना देगा, जिससे इन उपकरणों के अवैध कब्जे और पुनर्विक्रय को रोका जा सकेगा। यह पहल उन्नत निगरानी क्षमताओं के माध्यम से खोए हुए फोन को तेजी से वापस पाने में भी मदद करेगी।

आरपीएफ ट्रेनों और स्टेशन परिसर में खोई या चोरी हुई यात्री संपत्ति को वापस पाने के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। आरपीएफ के अभियान 'अमानत' का एकमात्र उद्देश्य कीमती सामान को उसके असली मालिकों को वापस करना है, जिसके प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच आरपीएफ ने ₹84.03 करोड़ मूल्य की खोई या पीछे छूटी वस्तुओं को सफलतापूर्वक बरामद किया और उन्हें 1.15 लाख से अधिक यात्रियों को वापस किया, यात्रियों ने रेलवे के प्रति आभार व्यक्त किया। रेलवे सुरक्षा संचालन में सीईआईआर को शामिल करने से आरएफपी के प्रयासों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे खोए या पीछे छूटे मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को वापस किया जा सकेगा।



- **'रेल मदद' के माध्यम से शिकायत पंजीकरण :** यात्री रेल मदद प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट ऑनलाइन या 139 डायल करके कर सकते हैं। यदि वे एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा।
- **आरपीएफ द्वारा सीईआईआर पंजीकरण :** आरपीएफ के जोनल साइबर सेल सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेंगे, आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे और उपकरण को ब्लॉक करेंगे।
- **निगरानी और रिकवरी :** एक बार खोए हुए फोन को नए सिम कार्ड के साथ पहचाने जाने के बाद, उपकरण के उपयोगकर्ता को इसे निकटतम आरपीएफ पोस्ट पर वापस करने की सलाह दी जाएगी।
- **मालिक को वापस करना :** उपकरण पुनः प्राप्त करने के लिए सही मालिक को सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- **कानूनी कार्रवाई :** गैर-अनुपालन के मामले में, एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और मामला जिला पुलिस को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **उपकरण से ब्लॉक हटाना :** पुनर्प्राप्ति के बाद, शिकायतकर्ता सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन से ब्लॉक हटाने का अनुरोध कर सकता है, यदि आवश्यक हो तो आरपीएफ की सहायता ली जा सकती है।

139

उपलब्धियाँ


कार्गो की मांग
बेरोकटोक शीघ्र ढुलाई
वित्त वर्ष 2024-25
1617.38 एमटी
वित्त वर्ष 2023-24
1590.67 एमटी
अप्रत्याशित मात्रा में ढुलाई
एमटी: मिलियन टन


रिकॉर्ड स्तर पर
स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग से
सुरक्षा और कार्यक्षमता
में वृद्धि
1376.75 आरकेएम
581.77 आरकेएम
136.64%
वित्त वर्ष 2023-24
वित्त वर्ष 2024-25
इससे ट्रेक की क्षमता बढ़ेगी और गतिशीलता में मिलेगी उन्नति


ऑटोमोबाइल से एमएमजी की आय
₹872.33 करोड़
₹788.44 करोड़
10.64%
वित्त वर्ष 2023-24
वित्त वर्ष 2024-25
लाभ में शानदार बढ़ोतरी


PM GatiShakti
लक्ष्य को मापने के लिए
नए युग की ओर बढ़ते कदम
100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स वित्त वर्ष 2024-25
उन्नत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी
माल ढुलाई प्रबंधन में तेजी और हैंडलिंग टाइम में कमी


कम कार्बन उत्सर्जन
के साथ हरित यात्रा
रेल परिवहन से CO_2 उत्सर्जन में 89% की कमी
सड़क
रेल
101 ग्राम
11.5 ग्राम
1 टन माल की 1 कि.मी. तक ढुलाई में CO_2 का उत्सर्जन


ट्रक्स-ऑन-ट्रेन (टीओटी)
12 घंटे में 630 कि.मी.
40% फास्टर डिलिवरी
कम कार्बन उत्सर्जन
पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई

भारतीय
पत्रिका की ऑनलाइन सदस्यता

STEP 1

ऑनलाइन सदस्यता हेतु www.irctc.co.in पर जाएं।

इस पेज के विज्ञापन (Promotions) पर जाएं।

आप सीधे www.irctctourism.com/ IRBRmag/#/home/hn पर भी जा सकते हैं।



❸ 'भारतीय रेल पत्रिका' पर क्लिक करें।

STEP 3

❶ इस बॉक्स में यदि आप के पास आईआरसीटीसी का लॉग-इन, पासवर्ड है तो उसका उपयोग करें।

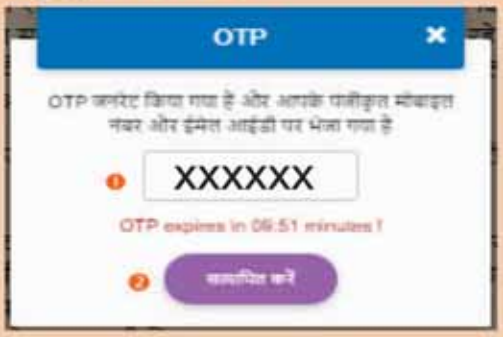


❷ लॉग-इन आईडी नहीं है तो गेस्ट लॉग-इन पर क्लिक करें।

❸ उसमें अपना ई-मेल तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें।

❹ सबमिट बटन दबाएँ।

STEP 5



❶ आपके पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर आए ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करें एवं

❷ सत्यापित करें

STEP 6



❹ पेमेंट मोड (कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, इंटरनेशनल कार्ड तथा आईपे) एवं

❷ पेमेंट गेट-वे का ऑप्शन पसंद करें

❸ मेक पेमेंट का बटन दबाएं

रेल
प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया

अब ई-पत्रिका भी उपलब्ध

STEP 2

1. यदि आप रेलकर्मी हैं तो 'हां' पर या रेलकर्मी नहीं हैं तो 'नहीं' पर क्लिक करें।
2. यदि 'हां' तो बॉक्स में अपना आरयूआईडी/आईडी/पीपीओ नंबर तथा एक आधिकारिक आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
3. 'भारतीय रेल' पत्रिका के लिए 'हिंदी' को और 'इंडियन रेलवेल' पत्रिका के लिए 'अंग्रेजी' में क्लिक करें।
4. इलेक्ट्रॉनिक मैग्ज़ीन के लिए, ई-मैग्ज़ीन पर क्लिक करें और हार्ड पत्रिका के लिए, फिजिकल बुक पर क्लिक करें
5. एक, दो या तीन यानि जितने साल की सदस्यता चाहते हैं, उस बिन्दु पर क्लिक करें।



6. नियम व शर्तों पर क्लिक करें तथा उसे ध्यान से पढ़ लें। यदि सहमत हों तो बॉक्स में टिक मार्क करें।

STEP 4



1. अपना पूरा पता पिन कोड के साथ दर्ज करें
2. सबमिट बटन दबाएँ।

STEP 7



1. पेमेंट मोड की डीटेल भरें
2. पेमेंट एमाउंट की जानकारी देखें।
3. संतुष्ट होने पर ही 'पे' बटन को दबाएं।
4. बैंक ओटीपी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पेमेंट सक्सेस फुल का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।

कृपया ध्यान दें

- पेमेंट के समय नियमानुसार ट्रांजेक्शन शुल्क लगते हैं, कृपया पेमेंट करते समय देख लें।
- पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको सदस्यता संबंधित जानकारी का एस.एम.एस. तथा मेल प्राप्त होगा।
- पेमेंट प्राप्त होते ही निर्धारित माह से आपको पत्रिका प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - 011- 47845378, 47845380 ईमेल: irbrhelp@gmail.com

भारतीय रेल ने बढ़ाई गति तथा क्षमता

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बहु-रेल लाइन, डीएफसी का किया विस्तार



वर्तमान में, 508 कि.मी. की मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना भारत में हाई-स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है, जिसके लिए जापान सरकार तकनीकी और वित्त सहायता प्रदान कर रही है।

अत्यधिक पूंजी लागत के कारण किसी भी हाई-स्पीड रेलवे (एचएसआर) गलियारे/परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि डीपीआर के परिणाम, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तपोषण विकल्पों जैसे संसाधनों की उपलब्धता।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों की गति और क्षमता बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित कामों/सर्वेक्षणों को किया जा रहा है-

दिल्ली-मुंबई खंड (1,386 कि.मी.)

- अनुभागीय गति को 160 कि.मी. प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कार्य को मंजूरी दी गई है और कार्य अग्रिम चरण में है।
- 1,386 कि.मी. मार्ग की लंबाई में से, 196 कि.मी. में 4 रेल लाइनें हैं और दहाणू रोड-विरार (64 कि.मी.) के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है।
- 1,126 कि.मी. के लिए संतुलन खंड में तीसरी और चौथी लाइन के लिए सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है।
- 1,404 कि.मी. पश्चिमी डीएफसी (दोहरी लाइन) को शुरू किया गया है और 102 कि.मी. के लिए संतुलन खंड में काम किया जा रहा है।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर (दोहरी लाइन) के निर्माण में 508 कि.मी. की लंबाई को शामिल किया गया है।

दिल्ली-हावड़ा खंड (1,450 कि.मी.)

- अनुभागीय गति को 160 कि.मी. प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कार्य को मंजूरी दी गई है और कार्य अग्रिम चरण में है।
- वर्तमान में, 1,450 कि.मी. मार्ग की लंबाई में से, 194 कि.मी. 4-लाइन खंड है, 312 कि.मी. 3-लाइन खंड है और शेष 944 कि.मी. दोहरी लाइन रेल अनुभाग है।

निम्नलिखित परियोजनाओं पर चल रहा है कार्य-

- सोन नगर की बहु रेल लाइन-अंडाल (375 कि.मी.)
- अलीगढ़-दाउद खान तीसरी लाइन (18 कि.मी.)
- मुगलसराय-इलाहाबाद तीसरी लाइन (150 कि.मी.)
- कालिपाहारी-बख्तरनगर 5वीं लाइन (18 कि.मी.)
- शक्तिगढ़-चंदनपुर चौथी लाइन (43 कि.मी.)
- नीमचा का विस्तार, अप लाइन से बचने के लिए (9.42 कि.मी.)

480 कि.मी. की तीसरी लाइन, 96 कि.मी. की चौथी लाइन और 151 कि.मी. की 5वीं लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है। पूर्वी डीएफसी (1,337 कि.मी.) को शुरू किया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना

भारतीय रेल में यात्री सुविधाओं में वृद्धि और सुधार की प्रक्रिया निरंतर है। तद्नुसार, रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है, जिसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें मास्टर प्लान की तैयारी और कई चरणों में उनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है, ताकि स्टेशन तक पहुँच, परिसंचारी क्षेत्रों, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट/एस्केलेटर जैसी आवश्यक सुविधाओं में सुधार किया जा सके। स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार प्लेटफॉर्म समतलीकरण और प्लेटफॉर्म पर कवर, स्वच्छता, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियॉस्क; प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, परिदृश्य निर्माण आदि।

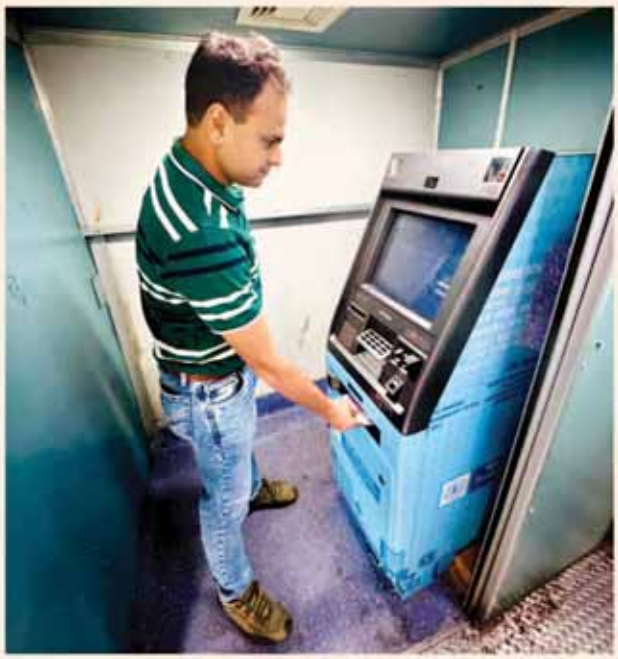
यह योजना निर्माण में सुधार की परिकल्पना करती है, जो शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करती है, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ, स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आदि की आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के



अनुसार तथा लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी-सेंटर का निर्माण। अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल अपनी सिग्नल प्रणाली को लगातार उन्नत करती है और आधुनिक बनाती है, जैसे बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, स्टेशनों के पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट्स (एलसी) आदि के इंटरलॉकिंग (एलसी) आदि। भारतीय रेल ने एक स्वचालित ट्रेन संरक्षण (एटीपी) प्रणाली के रूप में अग्रिम प्रौद्योगिकी प्रणाली 'कवच' का कार्यान्वयन किया है, जिसमें उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

भारतीय रेल की बड़ी पहल : ट्रेन में लगा देश का पहला एटीएम



भारतीय रेल ने तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली चलती ट्रेन में एटीएम मशीन लगाने का सफल परीक्षण किया है। यह ऐतिहासिक प्रयोग दिनांक 10 अप्रैल, 2025 को ट्रेन नं. 12110 मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अभिनव पहल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसमें यह बताया गया है कि ट्रेन के मिनी पैंट्री सेक्शन को इस एटीएम के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। रेल की मैकेनिकल टीम ने मशीन को रबर पैड और बोल्ट्स की मदद से इस तरह फिट किया है कि वह यात्रा के दौरान झटकों और कंपन से सुरक्षित रहे।

इस अनोखे प्रयोग का मकसद यात्रियों को ट्रेन सफर के दौरान नकदी निकालने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, रेलवे को किराये के अलावा अतिरिक्त आय का एक नया जरिया भी मिलेगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

निर्बाध कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़े शहर, मजबूत अर्थव्यवस्था को मिली गति



मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद और पूरे कॉरिडोर के आर्थिक परिदृश्य को बदलते हुए प्रमुख शहरों को एक एकीकृत आर्थिक शक्ति में जोड़ रहा है। यह हाई-स्पीड ट्रेन केवल तेज यात्रा के लिए ही नहीं है- यह विकास, निवेश और क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक है।

अहमदाबाद इस बदलाव का केंद्र है, क्योंकि यह कॉरिडोर पर एकमात्र ऐसा शहर है, जहाँ दो बुलेट ट्रेन स्टेशन हैं- साबरमती और अहमदाबाद। ये स्टेशन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ व्यापार के अवसरों को बढ़ाएंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में अहमदाबाद की स्थिति को मजबूत बनाएंगे।



दोनों स्टेशन स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित हैं और भारतीय रेल, मेट्रो नेटवर्क और बस सेवाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत होंगे, जिससे सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन के पूर्वी हिस्से में स्थित अत्याधुनिक साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब शहरी गतिशीलता को और अधिक सुव्यवस्थित करेगा, जिससे निर्बाध परिवहन संभव होगा और साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह एकीकृत परिवहन प्रणाली आर्थिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करेगी, जो अहमदाबाद को मुंबई और अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों से निर्बाध रूप से जोड़ेगी। अहमदाबाद से होकर गुजरने वाला 26 कि.मी. लंबा बुलेट ट्रेन मार्ग व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए पहुँच और गतिशीलता बढ़ेगी।

इस परियोजना के पूरा होने पर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंटरसिटी यात्रा को फिर से परिभाषित करेगा, यात्रा के समय को कम करेगा और परिवहन को और तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि-

- व्यापारिक जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार करके अहमदाबाद की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा।
- रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

- भीड़भाड़ कम होगी और शहरी गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे अहमदाबाद अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनेगा।
- विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन करके भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर महज एक परिवहन परियोजना नहीं है- यह आर्थिक प्रगति की आधारशिला है, जो अहमदाबाद के भविष्य को आकार देगी और इसे भारत की विकास गाथा में एक केन्द्रीय भूमिका में स्थापित करेगी।

प्रगति की स्थिति और तकनीकी विवरण

अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म संख्या 10, 11 और 12 के ऊपर बनाया जा रहा है और इसे लिफ्ट, सीढ़ियों और एस्केलेटर के माध्यम से कालूपुर मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। स्टेशन के प्रमुख संरचनात्मक कार्य, जिसमें कॉन्कोर्स, रेल और प्लेटफॉर्म स्लैब शामिल हैं, पूरा होने के करीब हैं, जबकि फिनिशिंग का काम चल रहा है।

इस बीच, मौजूदा साबरमती रेलवे यार्ड में स्थित साबरमती टर्मिनल स्टेशन को भारतीय रेल, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। स्टेशन पर संरचनात्मक कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म-स्तर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बुलेट ट्रेन वायाडक्ट अहमदाबाद जिले में 31 प्रमुख क्रॉसिंग को पार करेगा। इन संरचनाओं को कुशल और तेज निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्पैन-बाय-स्पैन विधि, फुल स्पैन लॉन्चिंग विधि और स्टील ब्रिज जैसी उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बनाया जा रहा है।

गुजरात में बुलेट ट्रेन

स्टील ब्रिज के पहले 100 मीटर स्पैन को किया गया लॉन्च

गुजरात के नडियाद के पास एनएच-48 (दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे) पर 2x100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज के पहले 100 मीटर स्पैन को लॉन्च किया गया।

इस 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज में 100 मीटर लंबे दो स्टील स्पैन शामिल हैं, जिन्हें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए एनएच-48 को पार करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है, जिनमें से एक स्पैन को को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

एनएच-48 छह लेन (प्रत्येक तरफ तीन लेन) वाला सबसे व्यस्त राजमार्ग है। ब्रिज के पहले स्पैन को एक छोर से लगभग 200 मीटर तक खिसकाकर तीन लेन के बीच राजमार्ग पर लॉन्च किया गया। इस व्यस्त राजमार्ग पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और सड़क उपयोगकर्ताओं के व्यवधान को कम करने के लिए, यह लॉन्चिंग प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से पूरी की गई।

इस स्टील ब्रिज के 100 मीटर स्पैन की ऊँचाई लगभग 14.6 मीटर, चौड़ाई 14.3 मीटर और वजन लगभग 1414 मीट्रिक टन है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास सालासर की कार्यशाला में निर्मित इस स्टील ब्रिज को 100 साल की अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया है।

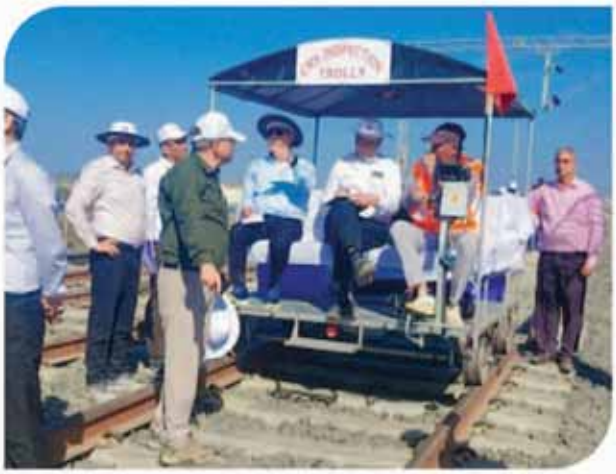
पुल का निर्माण लगभग 57,200 टोर-शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्टस, C5 सिस्टम पेंटिंग और इलास्टोमेरिक बियरिंग के साथ किया गया है। ब्रिज को अस्थायी ट्रेस्टल्स पर जमीन से 14.9 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित किया गया और इसे mac-alloy



bars का उपयोग करते हुए 2 semi-automatic जैक की स्वचालित प्रणाली से खींचा गया, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 टन है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 28 स्टील ब्रिज की योजना बनाई गई है। इनमें से 11 स्टील ब्रिज महाराष्ट्र में और 17 गुजरात में हैं। गुजरात में रेलवे/डीएफसीसी ट्रैक, राजमार्ग और भिलोसा इंडस्ट्री पर सात स्टील ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका हैं।

नयागाँव-खिलचीपुर तथा संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा नवनिर्मित रेल लाइन बनकर तैयार



मध्य वृत्त के रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा द्वारा निरीक्षण दिनांक 20 फरवरी, 2025 को रामगंजमण्डी से भोपाल नई लाइन परियोजना के अंतर्गत नयागाँव पुरा कुमारा-खिलचीपुर सेक्शन का निरीक्षण किया। साथ ही दिनांक 21 फरवरी, 2025 को भोपाल-रामगंज मंडी नई रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा सेक्शन का निरीक्षण किया। 276 कि.मी. रामगंजमंडी से भोपाल नई लाइन परियोजना की कुल लागत ₹3,035 करोड़ है।

नयागाँव-खिलचीपुर नई लाइन परियोजना : इस परियोजना में रामगंजमंडी से ब्यावरा स्टेशन 165 कि.मी. का परिक्षेत्र कोटा मंडल के दायरे में आता है। रामगंजमंडी से नयागाँव पुरा कुमारा स्टेशन 101 कि.मी. राजस्थान राज्य के अधीन एवं शेष स्टेशन मध्यप्रदेश राज्य में आता है। वर्तमान में घाटोली तक रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। अबतक रामगंजमंडी से खिलचीपुर कोटा मंडल के 165 कि.मी. में से 126 कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है। शेष कोटा मंडल का 39 कि.मी. का कार्य अगले वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। नयागाँव पुरा कुमारा-खिलचीपुर सेक्शन की कुल दूरी 22.32 कि.मी. है। सीआरएस मनोज अरोरा ने इस नवनिर्मित रेललाइन पर ट्रायल से पूर्व मोटर ट्राली एवं खिलचीपुर स्टेशन यार्ड का विधिवत निरीक्षण किया। सीआरएस ने नयागाँव पुरा कुमारा-खिलचीपुर सेक्शन में अधिकतम 130 कि.मी./घंटा की गति से स्पीड ट्रायल किया।

संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा नई लाइन परियोजना : इस परियोजना में भोपाल से ब्यावरा तक 111 कि.मी. का क्षेत्र भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि शेष खंड कोटा मंडल में आता है। वर्तमान में संत हिरदाराम नगर से निशातपुरा डी केबिन तक रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा सेक्शन की कुल दूरी 21 कि.मी. है। सीआरएस मनोज अरोड़ा ने इस नवनिर्मित रेललाइन पर ट्रायल से पूर्व मोटर ट्राली द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया, साथ ही जरखेड़ा स्टेशन यार्ड का विधिवत परीक्षण किया। सीआरएस ने संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा सेक्शन में अधिकतम 130 कि.मी./घंटा की गति से स्पीड ट्रायल किया।

भोपाल-रामगंजमंडी नई लाइन परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- इस परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल हैं एवं 5 जिले-भोपाल, सीहोर, राजगढ़, झालावाड़ और कोटा इससे जुड़े हुए हैं।
- यह लाइन माल और यात्री परिवहन दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण होगी, जिससे रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में 3 घंटे की बचत होगी।
- झालावाड़ (राजस्थान) के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की आवागमन लागत कम होगी।
- ब्यावरा-झालावाड़ मार्ग के बजाय यह नया मार्ग 42 कि.मी. छोटा होगा, जिससे ईंधन और समय की बचत होगी।
- घाटोली स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध केलकेरा मंदिर तक स्थानीय यात्रियों की पहुँच सुगम हो जाएगी।
- भोपाल मंडल में 111 कि.मी. रेल लाइन और 12 स्टेशनों के निर्माण के लिए ₹1,255 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- रूठियाई-कोटा-रामगंजमंडी-झालावाड़(257 कि.मी.)। जयपुर से दक्षिण की ओर जाने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट लगभग 115 कि.मी. कम हो जाएगा। परिणामी समय में 3 घंटे की बचत होगी।



क्षेत्रीय रेल एवं उत्पादन इकाइयों के समाचार

बरेका नागरिक सुरक्षा के दो सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार

दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में नागरिक सुरक्षा संगठन, बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के दो सदस्यों मार्कण्डेय मिश्रा, प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं चीफ वार्डन, नागरिक सुरक्षा और



राजेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत सीनियर सेक्शन इंजीनियर एवं वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा निरीक्षक, नागरिक सुरक्षा को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा संगठन में बेहतरीन सामाजिक कार्यों, अग्निशमन में अनुकरणीय एवं सराहनीय सेवा हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार (नागरिक सुरक्षा) वर्ष 2023 प्रदान किया गया, जिसे कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग/सामान्य, रेलवे बोर्ड अजीत कुमार झा द्वारा पुरस्कृत किया गया। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह एवं उप महाप्रबंधक एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अनुज कटियार ने इस उपलब्धि के लिए दोनों सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

महाप्रबंधक, एससीआर ने रेलवे अस्पताल, लल्लागुडा में विभिन्न सुविधाओं का किया उद्घाटन

अरुण कुमार जैन, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे ने दिनांक 13 मार्च, 2025 को केंद्रिय रेलवे अस्पताल, लल्लागुडा, सिकंदराबाद में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। महाप्रबंधक ने अस्पताल में ₹5.42 करोड़ की नई सीटी स्कैन सुविधा का उद्घाटन किया। नई सीटी स्कैन सुविधा सभी रेलवे लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक होगी और रेफरल व्यय को कम करने में भी मदद करेगी। उन्होंने एक औषधीय पादप उद्यान का उद्घाटन किया, जिसे अस्पताल परिसर में औषधीय पौधों की 20 किस्मों के साथ विकसित किया गया है।

इसके अलावा, महाप्रबंधक ने ओपीडी ब्लॉक की पहली मंजिल में एक फास्ट फूड कैंटीन का भी उद्घाटन किया, जो रेलवे लाभार्थियों की जरूरतें को पूरी होंगी। उन्होंने अस्पताल आने वाले



रेलकर्मियों की सुविधा के लिए डॉरमेट्री, सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने चार पहिया पार्किंग सुविधा का भी उद्घाटन किया।

आरडीएसओ अस्पताल में 38 अत्याधुनिक मोटरयुक्त बेड लगाए गए



आरडीएसओ अस्पताल अपने रोगियों और समुदाय के लाभ के लिए नवीनतम चिकित्सा प्रगति को अपनाने के लिए समर्पित है। इसी क्रम में आरडीएसओ अस्पताल में 38 अत्याधुनिक मोटराइज्ड बेड लगाए गए हैं। ये उन्नत बेड आधुनिक सुविधाओं जैसे कि समायोज्य ऊँचाई, बैकरेस्ट और लेग सपोर्ट पोजिशनिंग, आसान गतिशीलता और उपयोगकर्ता के अनुकूल रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के साथ आए हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने के दौरान रोगी के आराम और सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन बेडों की स्थापना से आरडीएसओ चिकित्सा लाभार्थियों को अधिक आरामदायक और सम्मानजनक इन-पेशेंट अनुभव प्रदान करके उच्च स्तर लाभ होने की उम्मीद है।

भारतीय रेल



डिजिटल घड़ियों की डिज़ाइनिंग के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता

प्रारंभ तिथि: 01.05.2025 **अंतिम तिथि: 31.05.2025**

प्रस्तुतिकरण विधि: उच्च–रिजॉल्यूशन वाली छवियाँ (न्यूनतम 300 डीपीआई, 2 एमबी से अधिक) बिना वॉटरमार्क या लोगो के **contest.pr@rb.railnet.gov.in** पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

मौलिकता: प्रस्तुतियाँ मौलिक होनी चाहिए, बौद्धिक संपदा उल्लंघनों से मुक्त होनी चाहिए और मौलिकता का प्रमाणन साथ में संलग्न होना चाहिए।

स्वामित्व: चयनित डिज़ाइनों का कॉपीराइट भारतीय रेल के पास रहेगा।

एक से अधिक प्रविष्टियाँ: अलग–अलग मौलिकता प्रमाणन के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं।

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	सांत्वना पुरस्कार
पेशेवर	₹5,00,000/-	50,000 रुपये प्रत्येक के 05 सांत्वना पुरस्कार
कॉलेज के छात्र (किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हों)		50,000 रुपये प्रत्येक के 05 सांत्वना पुरस्कार
स्कूली छात्र (12वीं कक्षा तक)		50,000 रुपये प्रत्येक के 05 सांत्वना पुरस्कार

अतिरिक्त लाभ: • सभी विजेताओं को मान्यता प्रमाणपत्र • प्रत्येक विजेता और उसके एक साथी को उनके घर से पुरस्कार समारोह स्थल तक आने–जाने के लिए निःशुल्क 3ए–क्लास रेलवे पास

महत्वपूर्ण दिशानिर्देश: • डिजाइन अभिनव, कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक होना चाहिए, तथा भारतीय रेल की भावना को प्रतिबिंबित करता हुआ होना चाहिए • प्रतिभागियों को अपने डिजाइन के पीछे के विचार को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त अवधारणा नोट (300 शब्दों तक) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है • किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी या कॉपीराइट उल्लंघन वाली प्रस्तुतियाँ अयोग्य घोषित कर दी जाएँगी

अधिक जानकारी और नियम व शर्तों के लिए भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाएँ।

पूर्वोत्तर सीमा रेल की एक अनोखी पहल : ड्रोन द्वारा की जा रही कामाख्या स्टेशन की सफाई



लाभ

- सफाई में दक्षता और सटीकता
- कोच और स्टेशन संरचनाओं के कठिन स्थानों तक पहुँच
- स्वच्छ और स्मार्ट रेलवे की ओर एक कदम

26 अप्रैल, 2025

चेन्नई बीच ↔ चेंगलपट्टू के बीच 12 कोच वाली पहली एसी ईएमयू



शहर की पहली 12 कोच वाली एसी ईएमयू चेन्नई बीच↔ चेंगलपट्टू के मध्य चलती है

आपकी यात्रा में तैयार

- स्वचालित दरवाजे–आसान प्रवेश–आसान निकास
- सीसीटीवी–ट्रैक पर हमेशा सुरक्षा
- पूर्ण एसी

19 अप्रैल, 2025

रायगढ़–कोटरलिया रेल खंड



सिर्फ एक पुराना ब्रिज नहीं बदला गया, बल्कि भविष्य को गति देने का कार्य किया गया है।

अब रायगढ़–कोटरलिया रेल खंड में ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा–दोनों ही नए स्तर पर पहुँची है।

28 अप्रैल, 2025

झांसी–बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना (152.57 कि.मी.)



134 कि.मी. कमीशन किया गया

लाभ

- बुंदेलखंड क्षेत्र के रेल नेटवर्क को मजबूत करना
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यात्री और माल यातायात को सरल बनाना
- झांसी, ललितपुर और बिना जिला के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाना

9 अप्रैल, 2025

आरओबी नं. 46 फलकनुमा, तेलंगाना



सुरक्षित रेल संरचना को मजबूत करने के लिए 4 समग्र स्टील गर्डर, प्रत्येक की लंबाई 36 मीटर, सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। इस परियोजना के पूरा होने से सुरक्षा में सुधार होगा और रेल-रोड यातायात में सहजता आएगी।

10 अप्रैल, 2025

ओपन वेब गर्डर स्पैन वाला पुल सफलतापूर्वक चालू किया गया



गति प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए और रेल संचालन को सुगम बनाते हुए, कटहल पखुरी और सिलनीबारी रेलवे स्टेशनों (असम) के बीच ओपन वेब गर्डर स्पैन वाला एक नया पुल सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित हुई है।

17 अप्रैल, 2025

सिवोक–रंगपो रेल परियोजना में सफल असेंबली और स्थापना



सिवोक–रंगपो रेल परियोजना के अंतर्गत, ब्रिज नंबर 15 पर 3x76.3 मीटर लंबे ओपन वेब गर्डर्स (कुल वजन 985 मीट्रिक टन) की 24 मीटर ऊँचाई पर सफलतापूर्वक असेंबली और स्थापना की गई है। इसके साथ, 13 में से 8 प्रमुख पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे सिक्किम की राष्ट्र के साथ रेल कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त हो रही है।

16 अप्रैल, 2025

विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में बायपास लाइन (26 कि.मी.)



लंबाई कमीशन की गई : 6 कि.मी.

लाभ

- महत्त्वपूर्ण रेल जंक्शन पर रेल परिचालन को सरल बनाना
- विजयवाड़ा स्टेशन पर मालगाड़ियों के लिए भीड़ कम करना

21 अप्रैल, 2025

खड़गपुर–आदित्यपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना (133.891 कि.मी.)



22 अप्रैल, 2025

लंबाई कमीशन की गई : 126.505 कि.मी.

लाभ

- हावड़ा–मुंबई ट्रंक मार्ग पर इस्पात और ऊर्जा संयंत्रों के लिए कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई में आसानी
- परिचालन क्षमता बढ़ाना

कामपुर रेलवे स्टेशन, असम स्थित एलसी गेट



कामपुर रेलवे स्टेशन (असम) पर गुवाहाटी–लमडिंग खंड के अंतर्गत स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट को सफलतापूर्वक रोड ओवर ब्रिज में बदला गया है, जिससे रेल यातायात में सुधार और सड़क यातायात भी सुगम हुआ है।

22 अप्रैल, 2025

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हो रहे रेलवे स्टेशन

आरसीकेरे जंक्शन, कर्नाटक



भौतिक प्रगति : 52%

कार्य पूरा

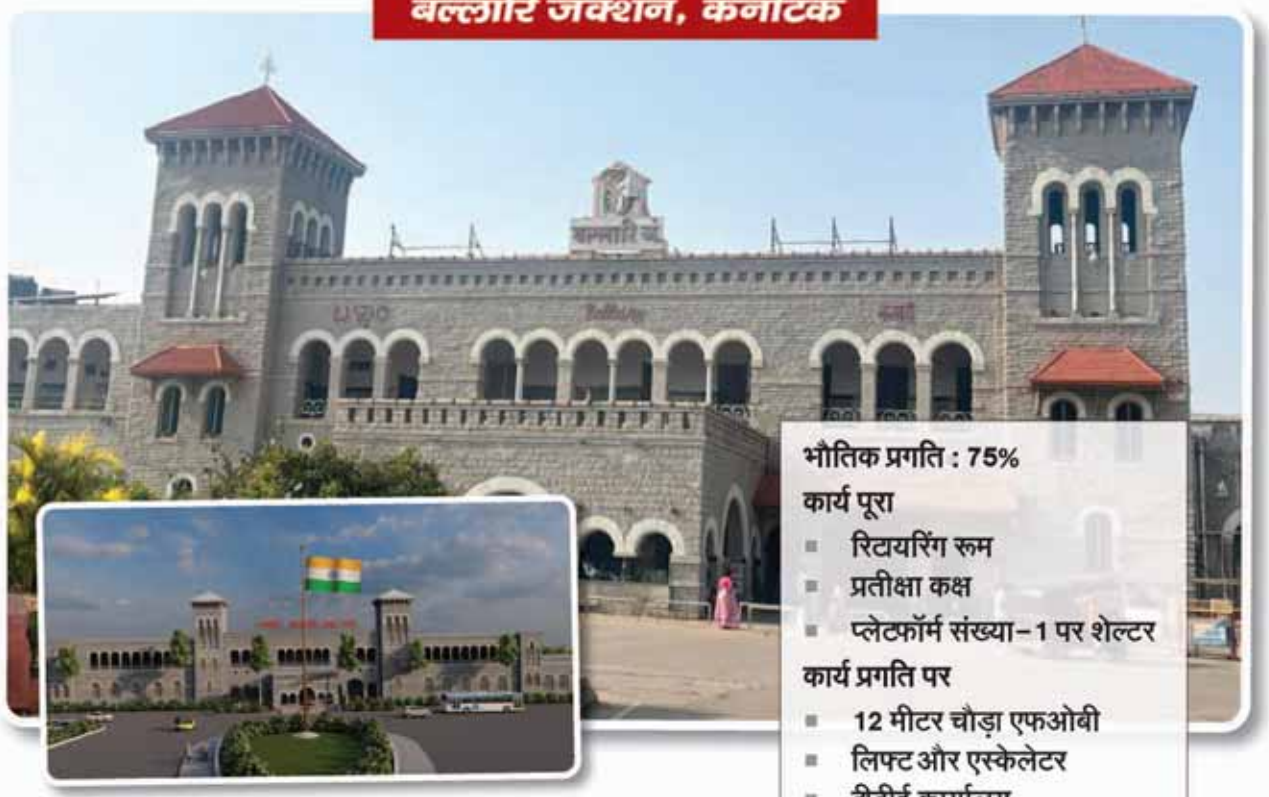
- सर्कुलेटिंग क्षेत्र
- पार्किंग और निकासी सड़क
- ऑटो स्टैंड के लिए फर्श

कार्य प्रगति पर

- नया फुट ओवर ब्रिज
- प्लेटफॉर्म और शेल्टर कार्य
- प्लेटफॉर्म के फर्श को फिर से बनाना

20 अप्रैल, 2025

बल्लारि जंक्शन, कर्नाटक



भौतिक प्रगति : 75%

कार्य पूरा

- रिटायरिंग रूम
- प्रतीक्षा कक्ष
- प्लेटफॉर्म संख्या–1 पर शेल्टर

कार्य प्रगति पर

- 12 मीटर चौड़ा एफओबी
- लिफ्ट और एस्केलेटर
- टीटीई कार्यालय

26 अप्रैल, 2025

बालाघाट रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश



भौतिक प्रगति : 78%

कार्य पूरा

- प्लेटफॉर्म पर कवर
- मुख्य अग्रभाग
- प्रवेश द्वार
- शौचालय
- चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग
- द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षा हॉल

कार्य प्रगति पर

- तीन पहिया वाहनों के लिए पार्किंग

29 अप्रैल, 2025

खम्मम रेलवे स्टेशन, तेलंगाना



भौतिक प्रगति : 45%

कार्य पूरा

- अस्थायी टिकट बुकिंग कार्यालय
- सामान्य प्रतीक्षालय

कार्य प्रगति पर

- 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज
- लिफ्ट और एस्केलेटर
- वातानुकूलित (एसी) लाउंज

17 मार्च, 2025

खेलों में भारतीय रेल



दिनांक 25 से 30 मार्च, 2025 के दौरान अमान, जॉर्डन में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय रेल के पहलवानों ने पदक जीते। फ्रीस्टाइल कुश्ती में उदित ने रजत, जबकि सुनील और नीतेश कुमार ने ग्रीको-रोमन कुश्ती में कांस्य पदक और महिला कुश्ती में अंतिम ने कांस्य पदक जीता।



मार्च, 2025 में तुर्की के अंताल्या प्रांत में आयोजित '2025 एफआईजी वर्ल्ड कप की महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक' स्पर्धा में वॉल्ट टेबल प्रतियोगिता में भारतीय रेल की जिम्नास्ट प्रणति नायक ने कांस्य पदक जीता।



हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब में आयोजित अंडर-18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर अपने समर्पण और जुनून का परिचय दिया है।



अर्जेंटीना में दिनांक 27 मार्च से 10 अप्रैल, 2025 तक आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में शूटर सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर देश और रेलवे का नाम रोशन किया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और रेलवे परिवार को गौरवान्वित करने वाले इस खिलाड़ी ने पूरे देश और भारतीय रेल का मान बढ़ाया है।



भारतीय रेल की शतरंज टीमों ने अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप-2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम बी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि टीम ए ने कांस्य पदक हासिल किया।

दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित 53वें सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भारतीय रेल की महिला हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता।



देहरादून में आयोजित नेशनल गेम्स, 2025



रवीना, सीसीटीसी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, का., बेंगलुरु, ने 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 20 कि.मी. रेस वॉकिंग स्पर्धा में नया खेल रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने दिनांक 11 फरवरी, 2025 को आयोजित प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

करिश्मा, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजी. का., बेंगलुरु, ने दिनांक 9 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

ऑल इंडिया रेलवे पुरुष हॉकी चैंपियनशिप संपन्न



दिनांक 1 मार्च, 2025 को रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला के सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली गई 82वीं ऑल इंडिया रेलवे पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद ने उत्तर रेलवे को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता को तीसरा जबकि पश्चिम रेलवे मुंबई को चौथा स्थान मिला। चैंपियनशिप नॉकआउट आधार पर खेली गई और इसमें भारतीय रेल की आठ टीमों ने भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह अध्यक्षता आरसीएफ के महाप्रबंधक एस. एस. मिश्र ने की।

मेट्रो की टीम ने 14वाँ युवा बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीता



दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च, 2025 तक इम्फा पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित 14वें युवा बास्केटबॉल टूर्नामेंट-2025 को जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में मेट्रो बास्केटबॉल टीम ने युवा बास्केटबॉल क्लब, भुवनेश्वर को हराया। मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी. उदय कुमार रेड्डी ने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सभी टीम सदस्यों को बधाई दी।

68वीं अखिल भारतीय रेल गोल्फ चैंपियनशिप में बरेका को रजत, रेल कोच फैक्ट्री बनी चैंपियन



बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के हरे-भरे गोल्फ कोर्स में 68वीं अखिल भारतीय रेल गोल्फ चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के तत्वावधान में एवं बरेका खेल संघ द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने गुब्बारे उड़ाकर किया।

इसमें भारतीय रेल के 21 क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों से कुल 66 खिलाड़ी भाग लिए। बरेका गोल्फ कोर्स, जो अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरम्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, इस आयोजन के लिए आदर्श स्थान है। मुख्य अतिथि नरेश पाल सिंह ने गोल्फ शॉट खेलकर प्रतियोगिता की रोमांचक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के खेल संवर्धन में योगदान और कर्मचारियों के खेलों के प्रति उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा, गोल्फ जैसी प्रतियोगिताएँ न केवल शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देती हैं, बल्कि रेलवे कर्मचारियों में अनुशासन, एकजुटता और खेल भावना को भी मजबूत करती हैं।

विरासत को संजोता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस



छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो भारतीय रेल की प्रगति और विकास का प्रतीक बनकर आज भी खड़ा है। इसे वर्ष 1878 से 1888 के बीच मास्टर आर्किटेक्ट एफ. डब्ल्यू. स्टीवंस की देखरेख और मार्गदर्शन में निर्मित किया गया था। इस वास्तुकला के अद्भुत चमत्कार की महानता को यूनेस्को ने वर्ष 2004 में मान्यता दी और तब से यह एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है।

यह भवन गोथिक शैली और भारतीय मुगल वास्तुकला शैली के सुंदर और संतुलित समावेश का उदाहरण है। यह सौंदर्य, भव्यता और रचनात्मकता का एक अद्भुत रूप प्रस्तुत करता है। इस संरचना में स्थानीय वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुंदर नक्काशियां की गई हैं। यह भवन समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी भारतीय रेल और मुंबई, दोनों के लिए एक बड़ी पहचान है।

125 वर्षों की प्रौद्योगिकी, प्रगति और विजय का उत्सव



बी-क्लास स्टीम लोकोमोटिव नंबर 782बी ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर प्राप्त किया। यह रेलवे की विरासत का प्रतीक, जो 125 वर्षों से सेवा में है, अब भी दृढ़ता से खड़ा है।

19 अप्रैल, 2025



दक्षिण पश्चिम रेलवे
समय और विरासत की एक यात्रा

बी. राधा रानी
जन संपर्क अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुब्बल्लि

भारत की कई सांस्कृतिक धरोहरों में से भारतीय रेल न केवल राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में बल्कि एक जीवंत विरासत के रूप में भी उभर कर सामने आती है, जो भारत के औद्योगिक और औपनिवेशिक अतीत की कहानियों को प्रतिध्वनित करती है। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को समूचे विश्व में 'विश्व धरोहर दिवस' मनाया जाता है, जिसे स्मारक स्थलों के लिए 'अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व और इसे संरक्षित करने की दिशा में आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है।

भारतीय रेल परिवहन का एक साधन होने से कहीं अधिक विश्व के सबसे बड़े और पुराने रेल नेटवर्कों में से एक है। यह एक व्यावसायिक सांस्कृतिक संस्था है, जिसका इतिहास 170 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। वर्ष 1853 में पहली यात्री ट्रेन से लेकर आज की हाई-स्पीड इनोवेशन तक भारतीय रेल ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।

इसकी भव्य वास्तुकला, दुर्लभ इंजन, औपनिवेशिक काल के स्टेशनों और सदियों पुरानी पद्धति दुनिया भर के इतिहासकारों, उत्साही लोगों और यात्रियों को अपनी ओर खींचती रही है।

भारतीय रेल के क्षेत्रीय रेलवे में से दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे), का मुख्यालय हुब्बल्लि, कर्नाटक में है। इसने भारतीय रेल की गौरवशाली विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

विश्व धरोहर दिवस मनाते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विरासत केवल भव्य स्मारकों और प्राचीन मंदिरों में ही नहीं अपितु स्टेशनों, इंजनों, प्रतीक्षालयों, सीटियों और यात्राओं में भी है– इन सभी को संस्थाओं द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित और प्रस्तुत

किया जाता है। हुब्बल्लि, मैसूरु और मालगुडी के रेल संग्रहालय इतिहास को जानने, बचपना को फिर से जीने और भारत की धड़कन को पुन: खोजने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

रेल संग्रहालय मैसूरु : भारत का प्रथम क्षेत्रीय रेल संग्रहालय

वर्ष 1979 में स्थापित मैसूरु में रेल संग्रहालय को भारत का प्रथम क्षेत्रीय रेल संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है, साथ ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के बाद देश का यह दूसरा रेल संग्रहालय है। प्रसिद्ध परिवहन संग्रहालय सलाहकार एम. जी. सातो ने इसके लिए प्रशंसनीय शब्दों में कहते हैं- यह आज केवल कलाकृतियों के भंडार-गृह के रूप में ही नहीं अपितु स्थानीय कल्पना और पहल के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी है।



विशेष भाप इंजन, मीटर गेज इंस्पेक्शन कार और दुर्लभ ऑस्टिन रेल कार से लेकर मैसूरु की तत्कालीन रियासत के शासकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शाही सैलून तक यह संग्रहालय भारतीय रेल इतिहास का एक गहरा व्यक्तिगत अध्याय प्रदर्शित करता है। इसके विशिष्ट व उत्कृष्ट संग्रहों में वर्ष 1932 का भाप से चलने वाला फायर इंजन और एक कोच कैफेटेरिया है, जहाँ आगंतुक आराम से बैठकर चिंतन-मनन भी कर सकते हैं।

वर्ष 2019-20 में संग्रहालय में एक विचारशील परिवर्तन के अंतर्गत आधुनिक सौंदर्यशास्त्र, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अभिकल्प और पारस्परिक कहानी कहने का संयोजन किया गया। संग्रहालय के प्रत्येक भाग को रास्ते से अब जोड़ा गया है, जो आगंतुकों को एक मनोरम और सुंदर वातावरण में भारतीय रेल के विकास के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। सिगनल और ट्रैक गैलरी, विंटेज स्टेशन सेटअप और सुरंगों और हरियाली के बीच दौड़ती हुई टॉय ट्रेन का सफर न केवल आनंददायक है बल्कि शिक्षाप्रद भी है।

आगंतुक प्राचीन सागौन और शीशम के बने फर्नीचर के बीच कॉफी की चुस्की लेने के साथ-साथ पुस्तकालय का भी भ्रमण कर सकते हैं या फिर दृश्य घर से मैसूरु शहर के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कला, मल्टीमीडिया और भूनिर्माण के उपयोग के साथ संग्रहालय न केवल रेलवे का बल्कि भारत की विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि का भी एक समुचित अनुभव प्रदान करती है।

प्रवेश द्वार के पास स्थित एक दुर्लभ कलाकृतियों की दुकान, जो सचमुच में एक अंतिम पड़ाव है, जहाँ से मेहमान मैसूरु रेल संग्रहालय के सुनहरी और पुरानी यादों को संजोने वाली स्मृतिचिह्न खरीद सकते हैं।

रेल संग्रहालय हुब्बल्लि : क्षेत्र की रेल विरासत

दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय के पास स्थित हुब्बल्लि रेल संग्रहालय, जिसका उद्घाटन वर्ष 2020 में किया गया है। यह कर्नाटक और व्यापक दक्कन क्षेत्र में रेलवे की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। आधुनिक ले-आउट वाला संग्रहालय होने के बावजूद यह इतिहास और पुरानी यादों की गहरी भावना को दर्शाता है।



इस संग्रहालय में सलीके से संरक्षित भाप और डीजल इंजन, विंटेज कोच और यांत्रिक सिगनलिंग उपकरण रखे गए हैं, जो एक समय में सुरक्षित और कुशल रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। संग्रहालय में रेलवे कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों, चीजें और परिचालन उपकरणों की एक शृंखला भी है, जो भारतीय रेल के पर्दे के पीछे के जीवन का सार प्रस्तुत करती है।



संग्रहालय में एक छोटी ट्रेन की सवारी, जो मनोरंजन और घर-परिवार जैसा माहौल प्रदान करती है, जबकि इंटरैक्टिव डिस्प्ले और गैलरी ऐतिहासिक संदर्भ और तकनीकी अंतर्दृष्टि दोनों प्रदान

करती हैं। हरा-भरा पथ और संरक्षित रोलिंग स्टॉक के साथ बाह्य प्रदर्शनी वाला क्षेत्र देखने में आकर्षक लगता है, जो अतीत की संरक्षित मशीनरी में भव्यता का स्पर्श लाता है।

हुब्बल्लि रेल संग्रहालय को, जो बात अलग बनाती है, वह है रेलवे विरासत को सुलभ, शैक्षिक और आकर्षक बनाने का इसका प्रयास। यह रेलकर्मियों की कहानियों, उनके द्वारा संचालित मशीनों और दक्षिण भारत में उनके द्वारा आकार देने में मदद की गई संस्कृति को जीवंत करता है। छात्रों, रेल के शौकीन लोगों और आम जनता के लिए यह संग्रहालय अतीत में प्रवेश का द्वार खोलती है, साथ ही रेल परिवहन की उभरती दुनिया की प्रशंसा करती है।

मालगुडी संग्रहालय अरसालु : कहानी और रेल विरासत का मिलन

दक्षिण पश्चिम रेलवे के विरासत के परिदृश्य में शायद सबसे अनोखा संग्रहालय मालगुडी संग्रहालय है, जो शिवमोगा के पास विलक्षण अरसालु रेलवे स्टेशन पर स्थित है। आर. के. नारायण के काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित इस स्टेशन पर प्रतिष्ठित भारतीय टीवी सिरीज मालगुडी डेज का फिल्मांकन हुआ है। एक उल्लेखनीय पहल के तहत इस परित्यक्त स्टेशन को विरासत संरक्षण के साथ-साथ पुरानी मर्मभरी यादों के साथ आकर्षक साहित्यिक और रेलवे संग्रहालय में बदल दिया गया है।



संग्रहालय में तस्वीरों, रंगमंच की सामग्री और लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज के दृश्यों के माध्यम से मालगुडी डेज की भावना को दर्शाया गया है। पुराने फर्नीचर, टिकट काउंटर और दीवार भित्ति चित्र छोटे शहर के लोगों के लिए रेल के प्रति आकर्षण को दर्शाते हैं, जो संग्रहालय की प्रदर्शनी की कहानी का केंद्र है।

लेकिन कल्पना से परे इतिहास छिपा है-संग्रहालय में ग्रामीण रेल परिचालन संबंधी प्रदर्शनी भी है, जो दूरदराज के शहरों और गांवों को जोड़ने में स्टेशनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। साहित्य और विरासत के इस दोहरे दृष्टिकोण से, मालगुडी संग्रहालय एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है, जो एक ओर भावनात्मक रूप से गूंजने वाला तो दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भी है।

यह संग्रहालय रेल विरासत के समारोह का आयोजन करने के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) ने इतिहास को अर्थात् जहाँ मूल रूप से यह रेलवे स्टेशन था, को संरक्षित कर एक उल्लेखनीय कदम आगे बढ़ाया है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे अपने कई रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने के लिए एक संगठित प्रयास कर रही है, साथ ही उनके मूल वास्तुशिल्प की मनोहरता और विरासत के मूल्य को भी संरक्षित कर रही है। यह उन्नयन केवल सुविधाओं में सुधार से नहीं अपितु इन स्टेशनों के इतिहास का सम्मान करने से भी संबंधित है।



केएसआर बेंगलुरु-चिक्कबल्लापुर-कोलार लाइन पर स्थित दोड्डजाल, देवनहल्लि, आवतिहल्लि और नंदी हॉल्ट जैसे सदियों पुराने रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, ताकि उनके मूल वास्तुशिल्प की सुंदरता और सांस्कृतिक महत्त्व को दर्शाया जा सके।

ये स्टेशन अपनी पुरानी वास्तुकला और औपनिवेशिक युग के निर्माण के साथ रेल यात्रा के बीते युग के मूक गवाह हैं। प्रत्येक संरचना की ऐतिहासिक सटीकता और सौंदर्य सार दोनों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए इनका जीर्णोद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के सहयोग से किया जा रहा है।

इस विश्व विरासत दिवस पर, दक्षिण पश्चिम रेलवे एक बड़ा प्रभावशाली संदेश देता है- हमारी विरासत को संरक्षित करना केवल अतीत को संरक्षित करने के बारे में नहीं है- यह विरासत को आगे बढ़ाने, हमारी सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करने और पीढ़ियों के बीच सेतु स्थापित करने के बारे में भी है। मैसूरु, हुब्बल्लि और अरसालु में खूबसूरती से बनाए गए संग्रहालयों से लेकर चालू देवनहल्लि और नंदी हॉल्ट जैसे कार्यस्थलों की सोची-समझी बहाली तक दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहल इस बात के शानदार उदाहरण हैं कि कैसे बुनियादी ढाँचा और विरासत एक साथ रह सकते हैं-संघर्ष में नहीं, बल्कि सद्भाव में।



कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन

एक जटिल एवं खूबसूरत रेल लाइन

विमलेश चंद्र
सेवानिवृत्त, रेल अधिकारी

जिस तरह से कोत्तवलसा-किरंडुल रेल लाइन को इनके स्टेशन के नाम के पहले अक्षर के आधार पर के-के लाइन कहते हैं, उसी तरह से कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन को के-आर रेल लाइन कहते हैं। के-के रेल लाइन को और के-आर रेल लाइन को जुड़वा रेलवे लाइन कहते हैं क्योंकि दोनों कोरापुट से शुरू होती हैं और अलग-अलग दिशा में चली जाती हैं लेकिन दोनों रेल लाइन बहुत ही खतरनाक और खूबसूरत रेल लाइन हैं।

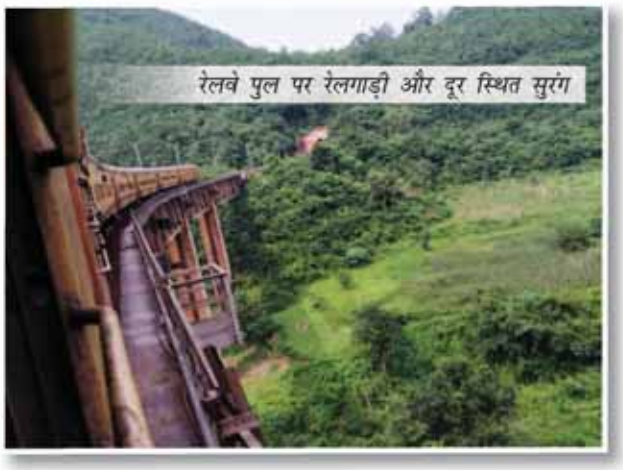
पिछले वर्ष दिनांक 6 अक्टूबर, 2024 को मैंने इस रूट पर यात्रा की थी तो उससे बहुत सारी रोचक जानकारी प्राप्त हुई थी।

कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था और इस रेल लाइन पर से यात्री रेलगाड़ी का संचालन दिनांक 31 अक्तूबर, 1995 को शुरू हुआ था। इस रेल लाइन की लंबाई 167 कि.मी. है। इस रेलवे सेक्शन में कुल 36 बड़े-बड़े रेलवे सुरंग हैं जबकि 76 बड़े रेल पुल हैं और 180 कर्व हैं। जब यह

पहले बनी थी, तब यह सिंगल रेल लाइन थी लेकिन अब थोड़ा सा सेक्शन छोड़कर बाकी सभी डबल रेल लाइन हो चुकी है। यह काफी पहले से ही विद्युतीकृत रेल लाइन है क्योंकि इस रेल लाइन से किरंडुल से जुड़े हुए क्षेत्र से आयरन अयस्क की ढुलाई होती है। यह पूरा घाट सेक्शन है। इसलिए यह काफी खतरनाक और घुमावदार वाली रेलवे लाइन है जो कि पूर्वी घाट पहाड़ी रेंज का हिस्सा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह रेलवे लाइन अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। रेल लाइन के दोनों किनारों पर बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और कहीं पर बहुत ही गहरी घाटी, देख कर डर लग जाता है।

सुरंगों और ऊँचे रेलवे स्टेशनों का बेजोड़ नमूना : कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन- मजेदार बात यह है कि कई जगह पर सुरंग और बड़े रेल पुल एक-दूसरे से जुड़े हैं। मतलब सुरंग पूरा हुआ तो तुरंत बड़ा पुल शुरू। उसके बाद दूसरा सुरंग शुरू। ऐसा कई जगह पर है। सुरंग और ऊँचे रेलवे स्टेशन का बेजोड़ नमूना है कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन। यह लंबी-लंबी रेल सुरंग और रेल पुल और काफी ऊँचे स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट से इसकी शुरुआत करें तो पहली सुरंग, बाईगुड़ा और काकिरिगुमा रेलवे स्टेशन के बीच आती है। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी सुरंग आती है। फिर टिकिरि के बाद लगातार सुरंग संख्या 5,6,7,8,9,10,11,12 आती हैं। फिर राउली स्टेशन आता है, जिसके दोनों किनारे पर सुरंग और ऊँचा पहाड़ है। राउली के बाद लगातार कुल 10 सुरंगें (सुरंग संख्या 13 से 22 तक) आती है। फिर लेलीगुम्मा स्टेशन के बाद सुरंग संख्या 23, 24, 25 आता है और फिर भालुमसका स्टेशन के बाद 26, 27, 28 नंबर सुरंग आता है। उसके बाद सिकरपाई स्टेशन के बाद सुरंग संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 आता है। उसके बाद 36 नंबर का अंतिम सुरंग केयुतगुड़ा स्टेशन के बाद अंतिम सुरंग, सुरंग संख्या 36 आती है। कोरापुट-रायगड़ा लाइन में कुल 36 रेल सुरंग हैं।

कोरापुट-रायगड़ा लाइन में सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई 1,599 मीटर और दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई 1,458 मीटर है। जबकि कोत्तवलसा-किरंडुल रेल लाइन में 446 कि.मी. लंबी



रेलवे पुल पर रेलगाड़ी और दूर स्थित सुरंग

रेल लाइन में कुल 58 रेलवे सुरंग हैं। जहाँ तक कोत्तवलसा-किरंडुल रेल लाइन सबसे लंबी रेल सुरंग की बात है। कोत्तवलसा-किरंडुल रेल लाइन में सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई 900 मीटर और दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई 701 मीटर है। अभी इस सेक्शन में 164 कि.मी. लंबी जो दूसरी नई रेल लाइन कोरापुट से सिंगापुर रोड तक बन रही है। उसमें कुल 24 सुरंग बन रहे हैं।



बाईगुड़ा रेलवे स्टेशन भवन

बाईगुड़ा रेलवे स्टेशन : सेक्शन का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन- कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन का सबसे अच्छा और सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन बाईगुड़ा रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन सबसे अच्छा स्टेशन है क्योंकि यह स्टेशन प्लेटफॉर्म से हटकर थोड़ा पीछे बना है और इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊँची पहाड़ी है। जैसा की कश्मीर रेलवे में बारामूला में है। मतलब स्टेशन भवन के पीछे खूबसूरत और ऊँचा पहाड़ होने से देखने में यह स्टेशन बहुत अच्छा लगता है। यह स्टेशन इस पूरे सेक्शन का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन भी है। इसकी ऊँचाई 925 मीटर है। जबकि कोत्तवलसा-किरंडुल लाइन का सबसे ऊँचा स्टेशन सिमलीगुड़ा का है, जिसकी ऊँचाई 996 मीटर है। यदि हम इसके रेल लाइन डायग्राम देखें तो ऐसा लगता है कि हर एक कि.मी. पर कोई न कोई कर्व है और सचमुच में ऐसा है भी लेकिन ऐसा कर्व क्यों है? वह इसलिए कि पूरी रेल लाइन पहाड़ के बेस पर मतलब पहाड़ के आधार पर किनारे-किनारे बनाया गया है।

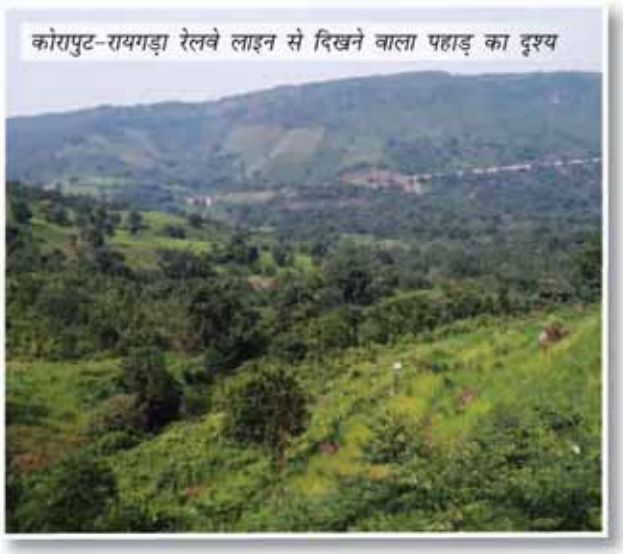
पहाड़ गोलाई लिए हुए सर्पीले आकर में है तो रेलवे लाइन भी सर्पीले आकर में है। मजेदार बात तो यह है की कई जगह जहाँ से रेलवे लाइन की कर्व शुरू होती है, वह रेल लाइन घूम कर वापस वहीं कुछ पास में आ जाती है। रायगड़ा-कोरापुट रेलवे लाइन पर राउली नाम का एक स्टेशन है, जिसके दोनों सिरों पर सुरंग और पहाड़ हैं। मतलब स्टेशन के दोनों सिरों पर, स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ही सुरंग की शुरुआत हो जाती है। राउली में रेल लाइन का एक बड़ा कर्व है। इस कर्व से राउली स्टेशन का पूरा लोकेशन दिखाई देता है। देश में ऐसे बहुत कम ही स्टेशन

हैं। कोंकण रेलवे का एक स्टेशन उक्शी है, जिसका प्लेटफॉर्म का सिरा 10 फीट जितना हिस्सा, सुरंग के अंदर है।

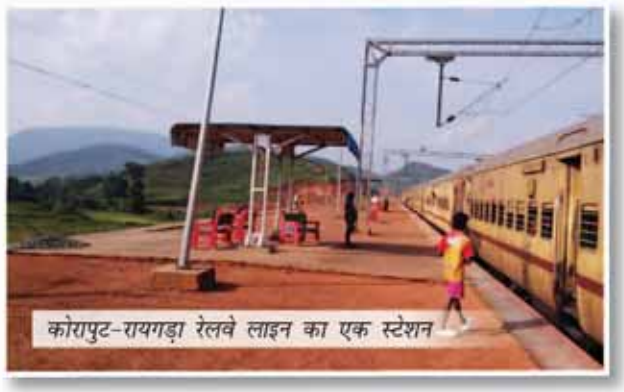


कोरापुट रेलवे स्टेश

रेलवे से जुड़े कई रिकॉर्ड : कोरापुट-रायगड़ा और कोत्तवलसा-किरंडुल रेलवे लाइन के नाम पर- कोत्तवलसा-किरंडुल रेलवे लाइन के नाम पर कई रिकॉर्ड हैं। जैसे कि शिमलीगुड़ा स्टेशन भारतीय रेल का बड़ी लाइन का सबसे ऊँचा स्टेशन था। मालीगुड़ा रेल सुरंग, सबसे ज्यादा ऊँचाई पर रेल सुरंग थी। मालीगुड़ा रेल पुल, सबसे ज्यादा ऊँचाई पर स्थित रेल पुल थी। मालीगुड़ा रेल सुरंग के ऊपर काफी ऊँचाई तक पहाड़ है। भारतीय रेल में शायद यह एक अनोखा रिकॉर्ड है। और तो और सबसे ऊँचा लेवेल क्रॉसिंग (LC) गेट भी यहीं पर थी। कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन में रायगड़ा में सबसे चौड़ा प्लेटफॉर्म है तो ऊँचे पुल और रेल पुल के साथ जुड़े सुरंग भी हैं। यद्यपि यह सब रिकार्ड अब कश्मीर घाटी रेलवे ने तोड़ दिया है।


कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन से दिखने वाला पहाड़ का दृश्य

भारतीय रेल का सबसे लंबा घाट सेक्शन और सबसे ज्यादा रेल सुरंगों वाला सेक्शन- दुनिया की सबसे लंबी घाट सेक्शन वाली रेलवे लाइन चीन में है जो कि हाई स्पीड वाली रेलवे लाइन है। जिस पर दुनिया की सबसे ऊँचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन स्थित है। जहाँ तक भारतीय रेल की बात है। भारतीय रेल में कुल 46 घाट सेक्शन हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7 घाट सेक्शन मध्य रेल में हैं और इन सभी में सबसे लंबा घाट सेक्शन पूर्व तटीय रेलवे के कोत्तवलसा-किरंडुल रेल लाइन में है, जिसकी लंबाई 188 कि.मी. है। जहाँ तक बड़ी रेल लाइन में सबसे ज्यादा रेल सुरंगों की बात है, कोंकण रेलवे में रोहा से ठोकुर स्टेशन के बीच 738 कि.मी. लंबाई में कुल 92 रेल सुरंग हैं। उसके बाद कोत्तवलसा-किरंडुल रेलवे में सबसे ज्यादा 58 रेल सुरंग और मंगलौर-हासन सेक्शन में 58 रेल सुरंग और कश्मीर घाटी रेलवे में 56 रेल सुरंग हैं। जबकि पाँचवे नंबर पर सबसे ज्यादा रेल सुरंग कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन पर हैं। जिनकी संख्या 36 है।


कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन का एक स्टेशन

कोरापुट-रायागड़ा रेल लाइन में अनोखा रेलवे कर्व- शायद ऐसी घुमावदार बड़ी रेल लाइन वाली कर्व, भारतीय रेल में बहुत ही कम हैं। वह इसलिए की पूरी रेल लाइन पहाड़ के बेस पर मतलब पहाड़ के आधार पर किनारे-किनारे बनाया गया है। पहाड़ गोलाई लिए सर्पीले आकार में है तो रेलवे लाइन भी सर्पीले आकार में है। मजेदार बात तो यह है कि कई जगह जहाँ से रेलवे लाइन की कर्व शुरू होती है। वह रेल लाइन घूम कर वापस वहीं कुछ पास में आ जाती है। राउली में रेल लाइन का एक बड़ा कर्व है। इस कर्व से राउली स्टेशन का पूरा लोकेशन दिखाई देता है। राउली वही स्टेशन है, जिसके दोनों सिरे पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और सुरंग हैं। सबसे मजेदार बात रेल पुलों की। जब 76 बड़े रेल पुल हैं तो छोटे रेल पुलों की क्या गिनती करना। इन रेल पुलों में एक बात जरूर आश्चर्य वाली है, वह यह है कि लगभग सभी बड़े रेल पुल एक जैसी डिजाइन वाले हैं। मतलब पुल में जो भी संरचना वाले सपोर्ट लगी है, वे सब के सब पुल के नीचे ही लगे हैं।

सिंगापुर रोड स्टेशन एक रोचक नाम वाला स्टेशन- वैसे तो सिंगापुर रोड स्टेशन और सिंगापुर देश में बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग मजाकिया तौर पर सिंगापुर रोड स्टेशन और सिंगापुर

देश को मिक्स करते हैं। यह स्टेशन भी, अपने शहर से 3 कि.मी. दूर है। यह एक रोचक नाम वाला रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा है तो सिग्नल को प्लेटफॉर्म के शुरुआत से 30-50 मीटर जितना अंदर स्थापित किया गया है। मतलब सिग्नल के बाहर भी 30-50 मीटर जितना प्लेटफॉर्म है।



रायगड़ा रेलवे स्टेशन देश का आठवाँ और ओडिशा का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन- रायगड़ा खूबसूरत और काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ का जो पुराना स्टेशन भवन है, वह छोटा है लेकिन अब नया स्टेशन भवन बहुत खूबसूरत और काफी बड़ा बन गया है। जहाँ सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ भारत का आठवाँ सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है, जिसकी लंबाई 910 मीटर है और यह प्लेटफॉर्म नंबर तीन है। इस प्लेटफॉर्म का विस्तार भी अभी पिछले साल में हुआ है। इस स्टेशन की एक रेलवे लाइन रायपुर से आती हुई पुरी स्टेशन के लिए जाती है और एक रेल लाइन सिंगापुर रोड होते हुए कोरापुट जाती है।

रायगड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा है। रायगड़ा का यह प्लेटफॉर्म 34 मीटर चौड़ा है। मतलब यह प्लेटफॉर्म लंबा भी है और खूब ज्यादा चौड़ा भी है। चौड़ाई के मामले में यह एक रिकार्ड है। रायगड़ा के नाम की स्पेलिंग भी मजेदार है। हर अक्षर के बाद आया हुआ है। यह एकदम पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है तो यह शहर भी खूबसूरत और साफ सुथरा है लेकिन यह छोटा शहर है। यहाँ आस-पास में कई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ कई एल्युमिनियम की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ मालगाड़ियों से बहुत कमाई होती है। इसीलिए रेलवे ने यह बड़ा स्टेशन बनाने का निर्णय लिया था। अप्रैल 2024 में यहाँ नया डीआरएम ऑफिस बनाने का टेंडर जारी हुआ था और अभी दिनांक 6 जनवरी, 2025 को यहाँ नए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन बनाने का शिलान्यास भी किया गया है। कुल ₹107 करोड़ से बनने वाला यह नया मंडल कार्यालय भवन लगभग एक वर्ष में बन जाएगा। नया मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन बनते ही यह नया मंडल भी बन जाएगा। यहाँ सब जगह हरियाली ही हरियाली है और ऊँची-ऊँची पहाड़ी भी। इस स्टेशन की शुरुआत दिसंबर 1931 में हुई थी। इस स्टेशन के विस्तार के अंतर्गत इस पूरे परियोजना (प्लेटफॉर्म, स्टेशन भवन, स्टेशन कंपाउंड इत्यादि) को रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाकर जनवरी 2024 में रेलवे को सौंपा है। इस तरह से रायगड़ा-कोरापुट रेल लाइन, भारतीय रेल के जटिल और खतरनाक रेल सेक्शन में से एक है।■

हम सभी का भारतीय रेल के साथ अटूट रिश्ता है

भारतीय रेल के साथ आप अपने संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लेख आदि हिन्दी में हमें भेज सकते हैं। पसंद आने पर रचनाओं को हम रेल मंत्रालय की आधिकारिक मासिक पत्रिका

भारतीय रेल

में प्रकाशित करेंगे

ई-मेल editorbhartiyarailrb@gmail.com

चयनित सामग्री/लेख की जानकारी ई-मेल द्वारा दी जाएगी,
प्रकाशित रचनाओं के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा

चिनाब रेल ब्रिज

राष्ट्र की संकल्प गाथा का अनमोल अध्याय

अद्भुत इंजीनियरिंग और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जम्मू-कश्मीर की घाटी को पहली बार ट्रेन से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली यह अभिनव कीर्ति

दिलीप कुमार

आजादी के समय भारत के अधिकांश क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हुए तो थे, लेकिन महत्त्व का जो क्षेत्र अलग-थलग था, वह था जम्मू-कश्मीर। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पहुँच से दूर था, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। फिर भी हिमालय की गोद में बसा यह रियासती प्रदेश दशकों तक भारतीय रेल नेटवर्क से कटा रहा। इस क्षेत्र को एक मजबूत रेल नेटवर्क से जोड़ना न केवल एक तकनीकी और भौगोलिक चुनौती थी, बल्कि एक भावनात्मक दूरी भी इसे राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करती रही। आज इस दूरी को एक महान राष्ट्रीय संकल्प, अद्भुत इंजीनियरिंग और दूरदर्शी नेतृत्व के द्वारा समाप्त किया जा रहा है और वह साधन है चिनाब रेल ब्रिज। भारतीय रेल द्वारा बनाया गया चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊँचा सिंगल-आर्च रेलवे ब्रिज है। यह जल्द ही जम्मू-कश्मीर की घाटी को पहली बार ट्रेन से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने जा रहा है।

दुनिया का सबसे उँचा ब्रिज

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना प्रतिष्ठित चिनाब रेल पुल न केवल एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि यह भारत के संकल्प, सामर्थ्य और रणनीतिक सोच का प्रतीक भी है। इस अद्वितीय परियोजना को पूरा होने में 20 वर्ष से अधिक का समय लगा और आज यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल बन चुका है। दुनिया के इतिहास में यह पुल भारत का गौरव बढ़ाएगा।

एफिल टावर से 35 मीटर ऊँचा यह स्टील आर्च पुल 359 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसे बक्कल और कौंड़ी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह पुल न केवल इन दो किनारों को जोड़ता है, बल्कि कश्मीर घाटी को भारत के रेल नेटवर्क से सीधे जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है।



पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

यह पुल 272 कि.मी. लंबे ऑल-वेदर रेल मार्ग का हिस्सा है, जो जम्मू से शुरू होकर कश्मीर घाटी तक जाएगा। इस मार्ग में कुल 38 सुरंगें और 927 पुल शामिल हैं- जो इस पूरे प्रोजेक्ट की तकनीकी जटिलता और महत्त्व को दर्शाते हैं। हालांकि इस रूट की पूरी तरह से शुरुआत के लिए कोई निश्चित समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है, लेकिन यह मार्ग भविष्य में क्षेत्रीय परिवहन, व्यापार और पर्यटन को नया जीवन देगा। अब तक कश्मीर में रेल सेवा केवल संगलदान से बारामूला तक ही सीमित थी। यह ब्रिज न केवल भौगोलिक दूरी को पाटता है, बल्कि यह भारत के सामरिक उद्देश्यों, क्षेत्रीय समावेश और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।

राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक

कश्मीर घाटी का सड़क संपर्क हर सर्दी में भारी बर्फबारी के कारण बाधित हो जाता है, जिससे क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। इस नई रेलवे लाइन से भारत को न केवल एक स्थायी और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि यह उसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बढ़त भी देगी। यह रेल लिंक भारत को 'पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन द्वारा किसी भी दुस्साहसिक प्रयास का प्रबंधन करने की क्षमता' प्रदान करेगा। यह पुल साल भर सैन्य उपकरणों और कर्मियों को सीमाओं तक पहुँचाने में सहायक होगा।

राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ

वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से, इस क्षेत्र में कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। रेलवे लिंक सहित 50 से अधिक सड़क, रेलवे और बिजली परियोजनाएँ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के विकास और एकीकरण को गति देना है, लेकिन रोजगार, व्यापार और बेहतर कनेक्टिविटी के नए अवसर भी लाएगी।

चिनाब रेल पुल जैसे मेगा प्रोजेक्ट न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का है, बल्कि क्षेत्रीय रोजगार का बड़ा स्रोत भी साबित होगा। पुल निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को सीधे व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपोर्ट, होटलिंग, कंस्ट्रक्शन सप्लाई जैसी सहायक गतिविधियाँ भी सक्रिय हुईं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली।

व्यापार : यह पुल कश्मीर घाटी को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने में मदद करेगा। फल, सब्जी, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पाद अब अधिक समय और लागत की बचत के साथ नए बाजारों तक पहुँच सकेंगे। इससे कश्मीरी किसानों और व्यापारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

कनेक्टिविटी : रेल कनेक्टिविटी एक समावेशी विकास की नींव होती है। चिनाब पुल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के बीच अब वर्ष भर निर्बाध संपर्क संभव हो पाएगा, जो सर्दियों में सड़क अवरोध के कारण अब तक संभव नहीं था। साथ ही, यह पुल देश की सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को तेज आवाजाही की सुविधा भी देगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी।

निर्माण की चुनौतियाँ

चिनाब पुल को वर्ष 2003 में मंजूरी मिली थी, लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया कठिनाईयों से भरी रही। हिमालय की दुर्गम भौगोलिक स्थितियाँ, संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र, संकरी सड़कें और सीमित पहुँच, सभी ने इसे इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। शुरुआती चरणों में इंजीनियरों को निर्माण स्थल तक पैदल या खच्चरों के सहारे पहुँचना पड़ता था। ब्रिज को 266 कि.मी./घंटा तक की आंधियों और संभावित विस्फोटों को सहन करने योग्य बनाया गया है। इसमें प्रयुक्त संरचना विस्फोट-रोधी है और यह 40 किलो टीएनटी तक के विस्फोट को सहन कर सकती है।



आर्थिक संभावनाएँ

इस रेलवे परियोजना के पूरा होने से कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। कश्मीर के 70% से अधिक लोग कृषि और विशेष रूप से नष्ट हो सकने वाले फलों की खेती पर निर्भर हैं। सर्दियों में खराब सड़क संपर्क के कारण फल और अन्य उत्पाद समय पर देश के बाजारों तक नहीं पहुँच पाते, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

रेलवे संपर्क से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में भेजे जाते हैं। लेकिन इस तरह की व्यापार शृंखला बढ़ाने से वहाँ आर्थिकि संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। चिनाब ब्रिज के माध्यम से रेलवे से दक्षिण भारत के बाजारों तक सीधी पहुँच भी संभव हो सकेगी। हालाँकि, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस ब्रिज से इस दिशा में भी नई राह खुलेगी।

हालांकि पुलवामा के किसानों का यह कहना है कि सबसे नजदीकी स्टेशन 50 कि.मी. दूर है और इतनी दूरी तक माल को पहुँचाना, फिर ट्रेन में लोड करना, नष्ट हो सकने वाले उत्पादों के लिए व्यवहारिक नहीं है। जब तक स्थानीय सड़क और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बेहतर नहीं किया जाता, तब तक रेलवे से पूरी तरह लाभ मिलना संभव नहीं होगा। भारतीय रेल लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी मजबूत बना रहा है।

पर्यटन में संभावनाएँ

रेलवे संपर्क से कश्मीर में पर्यटन को भी नया जीवन मिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य ने देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है। जम्मू



और श्रीनगर के बीच सीधी और सस्ती रेल सेवा यात्रा के समय को आधा कर देगी, जिससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। बेहतर परिवहन सुविधा से नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी। रियासी जिला, जहाँ त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। हर साल यहाँ लगभग एक करोड़ तक पर्यटक पहुँच जाते हैं। उन्होंने जिले की ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों, जैसे शिव खोड़ी, सलाल डैम और भीमगढ़ किले को और अधिक पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। इस कनेक्टिविटी से रियासी जिले को एक समृद्ध पर्यटन केंद्र में बदला जा सके।■



भारतीय ज्ञान पद्धति की प्रशासनिक उपयोगिता

डॉ. अच्युतानन्द झा
महानिरीक्षक, रेल सुरक्षा बल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, खड़गपुर

भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के प्रारंभ से लेकर प्राचीन काल एवं मध्य काल में ज्ञान, कौशल एवं क्षमता के विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ज्ञान एवं कौशल क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को इंडिक नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान पद्धति के नाम से जाना जाता है। भारतीय ज्ञान पद्धति का व्यापक क्षेत्र है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, दर्शन, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। इतना ही नहीं भारतीय ज्ञान पद्धति में युद्ध पर विचार है तो शांति पर भी, अपराध पर विमर्श है तो न्याय की व्यवस्था भी है। भारतीय ज्ञान पद्धति में आकाश जैसा विस्तार है तो सागर जैसी गहराई भी है।

भारतीय ज्ञान पद्धति मध्यकाल में मध्य एशिया के आक्रांताओं से हाशिये पर चली गई थी। औपनिवेशिक काल में सत्ताधीशों ने पश्चिमी ज्ञान पद्धति को बेहतर बताते हुए, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने और स्वार्थ सिद्धि हेतु भारतीय ज्ञान पद्धति को अंधकार युग में पहुँचा दिया था। परंतु भारतीय ज्ञान पद्धति की एक क्षीण धारा निरंतर प्रवाहित होती रही। 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि के प्रयासों से यह विकसित होती रही। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद के विचारों को हमारी भारतीय ज्ञान पद्धति के एक अंग के रूप में प्रशंसित रूप से मान्यता मिली। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आत्मा को जाग्रत रखा गया। आजादी के उपरांत भारत का राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ को अपनाया गया जो प्राचीन मौर्यकालीन शिल्प, तकनीक एवं उत्कृष्ट विज्ञान का जीवित प्रमाण है। परंतु कालक्रम में आजाद भारत में भी भारतीय ज्ञान पद्धति को मुख्यधारा में लाने हेतु समुचित एवं सम्यक प्रयास, संस्थागत रूप से नहीं किया गया। परिणामतः इसका पुनर्स्थापन नहीं हो पाया। नई शिक्षा नीति 2020 में इसे समुचित स्थान उपलब्ध कराया गया। आज हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं।

भारतीय ज्ञान पद्धति में वेद है, श्रुति है, स्मृति है, भाष्य है। यह साहित्यिक भी है और गैर साहित्यिक भी। प्राचीन भारत में गणितशास्त्र पर लिखित महत्त्वपूर्ण पुस्तक लीलावती काव्य शैली में है, इसी प्रकार योगदर्शन की पुस्तक पद्य स्वरूप में है। समग्रतः इस पद्धति को चतुर्दश विद्या स्थान कहते हैं। इसका अर्थ उन चौदह प्रकार की विद्या (ज्ञान के विषय) से है, जिन्हें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया था। ये विद्या क्षेत्र शास्त्रों और व्यावहारिक जीवन के ज्ञान को संगठित करते हैं और इनका अध्ययन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया था।

भारतीय ज्ञान पद्धति के प्रमुख अंग

1. **चतुर्दश विद्या स्थान**- इस पद्धति में छह वेदांग (वेदों के सहायक अंग) और आठ प्रकार की विद्याएँ हैं।

1.1 **छह वेदांग**- इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द तथा ज्योतिष विधा शामिल हैं। वेदों के अध्ययन और सही समझ के लिए छह वेदांग अत्यंत महत्त्वपूर्ण माने गए हैं। शिक्षा : शब्दों और स्वरों के सही उच्चारण का ज्ञान। कल्प : धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का अध्ययन। व्याकरण : भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन। पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। निरुक्त : शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ का ज्ञान। छन्द : वेदों के छंदों की संरचना का अध्ययन। ज्योतिष : खगोल विज्ञान और कालगणना का ज्ञान।

1.2 **आठ विद्या क्षेत्र** : इसमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र शामिल हैं। ये विद्या क्षेत्र सामाजिक, धार्मिक और व्यावहारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। पुराण: ऐतिहासिक कथाओं और धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह। न्याय : तर्कशास्त्र और सही दृष्टिकोण की खोज। मीमांसा : वेदों की व्याख्या और धर्म के सिद्धांत। धर्मशास्त्र : समाज के आचरण और नियमों का अध्ययन। आयुर्वेद : स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान। धनुर्वेद : सैन्य विज्ञान और युद्धकला। गंधर्ववेद : संगीत और कला का शास्त्र। अर्थशास्त्र : शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का ज्ञान।

2. भारतीय दर्शन और प्रशासनिक दृष्टिकोण

भारतीय ज्ञान पद्धति के विभिन्न 6 दार्शनिक सिद्धांत जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन आज भी शासन और प्रशासन के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उदाहरणस्वरूप :

2.1 **न्याय दर्शन** : सही दृष्टिकोण, तर्क और प्रमाण पर आधारित निर्णय लेने में सहायक।

2.2 **सांख्य दर्शन** : त्रिगुण सिद्धांत (सत्त्व, रजस्, तमस्) के माध्यम से निर्णय और नेतृत्व क्षमता को संतुलित करने का दृष्टिकोण।

2.3 **योग दर्शन** : योग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक एकता, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त शुद्धि आदि के द्वारा नैतिक आचरण एवं नेतृत्व क्षमता में संवृद्धि होती है।

2.4 **मीमांसा दर्शन** : नैतिकता और अनुशासन पर आधारित कर्म और धर्म का सिद्धांत।

2.5 **वैशेषिक दर्शन** : यह एक ऐसा दर्शन है जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भौतिक जगत और उसके तत्त्वों का विश्लेषण करता है।

2.6 **वेदांत दर्शन** : इस दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा में एकता एवं समानता को रेखांकित किया गया है। इससे प्रशासनिक निर्णयों एवं अनुपालन में सभी के प्रति समभाव के महत्त्व को दर्शाता है।

3. पंचऋण और प्रशासन

भारतीय ज्ञान पद्धति में पंचऋण (देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण, भूतऋण और नरऋण) की अवधारणा मानव जीवन की जिम्मेदारियों का प्रतीक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये सिद्धांत आधुनिक नीतियों में समावेश किए जा सकते हैं :

3.1 **देवऋण** : देवऋण के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक तंत्र को अपने कर्तव्यों और नैतिकता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। देवताओं को सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ मानते हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी समाज के प्रति उच्च आदर्शों और पारदर्शिता को अपनाकर नीतियों का क्रियान्वयन करें।

3.2 **ऋषिऋण** : ऋषिऋण ज्ञान और शिक्षा के प्रति ऋण है। प्रशासनिक व्यवस्था को इस सिद्धांत से प्रेरणा लेकर समाज में शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए।

3.3 **पितृऋण** : पितृऋण पूर्वजों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। यह ऋण प्रशासनिक अधिकारियों को प्राचीन धरोहरों और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है।

3.4 **भूतऋण** : भूतऋण का तात्पर्य प्रकृति, जीव-जंतुओं और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी से है। प्रशासनिक तंत्र को पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

3.5 **नरऋण** : नरऋण समाज और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्रशासन का मुख्य कर्तव्य जनता की सेवा करना है। यह ऋण प्रशासन को समाज के प्रति संवेदनशीलता, समानता और कल्याणकारी नीतियों के प्रति जागरूक करता है।

4. पंचमहाभूत और प्रशासनिक उपयोगिता

भारतीय ज्ञान पद्धति एवं दर्शन के पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) का प्रशासनिक और पर्यावरणीय संदर्भ में भी गहरा महत्त्व है।

4.1 **पृथ्वी** : पृथ्वी तत्त्व भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। प्रशासन को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भूमि का दुरुपयोग न हो और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग किया जा सके। इस संदर्भ में अथर्ववेद में उल्लेखित पृथ्वी सूक्त अति महत्त्वपूर्ण है, यह सूक्त निम्नवत है –

पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद

यास्यां विश्वानि भूतानि वसन्ति सहोजसः।
सा नो भूमिः प्रथतां च नः।।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।
परिवृतोऽस्मि ऋतेन।।

या स्वभावा विश्वधाया विश्वमाभार्या।
सा नो भूमिः प्रथतां च नः।।

यस्यां जातोऽहं यास्यामूतिर्यायं।
सा नो भूमिः प्रथतां च नः।।

या नो भूमिर्बह्वानं स्वपत्यं क्षमवत्तरा।
सा नो भूमिः प्रथतां च नः।।

अनुवाद

जिस पृथ्वी पर सभी प्राणी अपनी शक्ति से निवास करते हैं।

वही पृथ्वी हमारे लिए स्थिर और विस्तृत रहे।

पृथ्वी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ।

मैं सत्य और धर्म से घिरा हुआ हूँ।

जो पृथ्वी सभी जीवों का धारण करती है और सबका पोषण करती है, वही पृथ्वी हमारे लिए स्थिर और विस्तृत रहे।

जिस पृथ्वी पर मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ मेरी अंतिम गति होगी,

वही पृथ्वी हमारे लिए स्थिर और विस्तृत रहे।

जो पृथ्वी हमारी मातृभूमि है, वह हमें शक्ति और संतान देती है,

वही पृथ्वी हमारे लिए सहनशील और विस्तृत रहे।

4.2 **जल** : जल जीवन का मूल तत्त्व है। प्रशासन का दायित्व है कि जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन करे और जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करे। यह प्रशासनिक कार्यों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

4.3 **अग्नि :** अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है और आधुनिक प्रशासन में इसका अर्थ ऊर्जा संसाधनों और आपदा प्रबंधन से जुड़ा है। प्रशासन को ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की प्रभावी योजनाएँ बनानी चाहिए ताकि आग, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके।

4.4 **वायु :** वायु जीवन का अभिन्न अंग है। प्रशासन को वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन आवश्यक है।

4.5 **आकाश :** आकाश तत्त्व आधुनिक प्रशासन में संचार, अंतरिक्ष और आकाशीय संसाधनों से जुड़ा हुआ है। प्रशासन को संचार प्रणाली, आकाशीय क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि तकनीकी प्रगति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

5. प्राचीन साहित्य और आधुनिक प्रेरणा

भारतीय साहित्य, जैसे पंचतंत्र, प्रशासन और नेतृत्व के लिए अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। उदाहरणस्वरूप –

5.1 नीतिगत निर्णय (Policy Making And Decision Making)

पंचतंत्र की कहानियाँ : नीति-निर्माण में विवेक और दूरदर्शिता का महत्त्व सिखाती हैं।

सिंह और सियार' की कहानी में दिखाया गया है कि सियार की चतुराई ने सिंह को ठगा, जिससे सीख मिलती है कि शासक या प्रशासक को किसी भी सलाह या सुझाव को सत्यापित करने के बाद ही क्रियान्वित करना चाहिए।

प्रशासनिक सबक : कुशल प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए लेकिन हर निर्णय को अच्छी तरह से सोच-विचार के बाद ही लागू करना चाहिए।

5.2 संकट प्रबंधन (Crisis Management)

'कबूतर और शिकारी' की कहानी संकट के समय सामूहिक प्रयास और एकता से मुसीबत से बचने का सबक देती है। प्रशासकों को भी टीम वर्क और सहयोग से समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

प्रशासनिक सबक : प्रशासनिक अधिकारियों को संकट के समय धैर्य, बुद्धिमत्ता और टीमवर्क के साथ काम करना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

5.3 नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills)

'बूढ़ा शेर और चालाक खरगोश' की कहानी सिखाती है कि एक छोटा खरगोश भी बुद्धिमानी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। नेतृत्व में शक्ति से ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।

प्रशासनिक सबक : एक सफल प्रशासक या नेता वह होता है जो अपनी टीम का विश्वास जीतता है और कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रशासनिक नेतृत्व में मानवीय गुणों का होना भी आवश्यक है।

5.4 धोखे और चालबाजी से बचाव (Avoiding Deception and Manipulation)

'धोखेबाज बगुला और केकड़ा' की कहानी धोखाधड़ी से सावधान रहने और विवेक का प्रयोग करने का सबक देती है। यह प्रशासन में विश्वासघात से बचने की ओर इशारा करती है।

प्रशासनिक सबक : एक कुशल प्रशासक को चतुराई और धोखे की पहचान होनी चाहिए, ताकि वह अपने कर्मचारियों और नीतिगत मामलों में सही निर्णय ले सके और किसी भी छल से बच सके।

5.5 सही सहयोगियों का चयन (Choosing the Right Allies)

'बंदर और मगरमच्छ' की कहानी यह सिखाती है कि किस प्रकार मित्रता का चुनाव समझदारी से करना चाहिए और धोखे से बचना चाहिए।

प्रशासनिक सबक : प्रशासनिक अधिकारियों को टीम का चुनाव करते समय सक्षम, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सहयोगियों का चयन करना चाहिए। गलत या अयोग्य लोगों से बचकर, सही लोगों के साथ काम करने से प्रशासनिक सफलता मिलती है।

5.6 आत्मसंयम और धैर्य (Self-control And Patience)

'कौआ, साँप और नेवला' की कहानी दिखाती है कि संयम और योजना बनाकर बड़े से बड़े संकट को हल किया जा सकता है।

प्रशासनिक सबक : प्रशासन में आवेग के स्थान पर धैर्य का महत्त्व होता है। प्रशासकों को बिना उत्तेजित हुए, हर स्थिति का संतुलित और धैर्यपूर्वक समाधान करना चाहिए।

6. भारतीय ज्ञान पद्धति : मूल तत्त्व और उद्देश्य

भारतीय ज्ञान पद्धति का मूल तत्त्व 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' है। यह 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना पर आधारित है और भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकता को भी संतुलित करती है। जहाँ पश्चिमी ज्ञान पद्धति समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे (Equality, Liberty, Fraternity) पर जोर देती है, वहीं भारतीय पद्धति इन सिद्धांतों के साथ मोक्ष (Liberation) को भी अपने

केंद्र में रखती है। भारतीय ज्ञान पद्धति केवल भौतिक उन्नति का ही नहीं, बल्कि मानवीय और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

भारतीय ज्ञान पद्धति में निष्काम कर्म, परोपकार, संस्कार, पंचमहाभूत, पंचऋण, पंचकोष, ज्ञान-मार्ग और भक्ति-मार्ग इन सभी को मिलाकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी का निर्माण करती है। इन अवधारणाओं को समाहित करने वाले विपुल साहित्य उपलब्ध हैं। यह एक लंबी सूची है। उदाहरणस्वरूप- गणितशास्त्र एवं ज्योतिषशास्त्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त की रचनाएँ, आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, विभिन्न वास्तुशास्त्र, कला एवं सौंदर्यशास्त्र में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, विधि में याज्ञवलक्य स्मृति, व्याकरण में अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनायें, कृषि में कृषि पराशर, चाणक्य नीति, पतंजली का योगशास्त्र, महाभारत में चक्रव्यूह का वर्णन, हितोपदेश, थिरुवल्लूवर रचित थिरुक्कुरल। सामवेद में संगीत, मंदिर स्थापत्य कला, राजधर्म संबंधी अवधारणा, पशु आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, जातक कथायें, पंचतंत्र, पंचांग इत्यादि हैं।

'परोपकार' इस ज्ञान परंपरा का मूल संदेश है, जैसा कि महर्षि वेदव्यास और तुलसीदास के ग्रंथों में वर्णित है :

'परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम्।'

रामचरितमानस

परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।
निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर।

(रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड 7.41)

निष्कर्ष : उपर्युक्त चौपाई के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान पद्धति में देश तथा विश्व को विकसित करने के सूत्र उपलब्ध हैं। वर्तमान उत्तर आधुनिक काल को VUCA-Volatile Uncertain Complex and Ambiguity के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। ZEN ZAND ZENALFA का झुकाव STEM-SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING AND MATHEMATICS के प्रति अत्यधिक है। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान पद्धति का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। नई शिक्षा नीति, शिक्षण संस्थानों, मिशन कर्मयोगी के पहल से हम, भारतीय ज्ञान पद्धति के मूल तत्त्वों एवं अवधारणाओं को आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक काल में हुए विकास से सबंद्ध कर सकते हैं।

भौतिकवाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद की तुलना में भारतीय ज्ञान पद्धति एक Sustainable Development का समावेश करती है। इसके लिए भारत की प्राचीन जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है। इस पद्धति को हाशिये से मुख्य धारा एवं अमृत काल की योजनाओं का अंग बनाने हेतु भारतीय ज्ञान पद्धति को शासन एवं प्रशासन में शामिल करके भारत को 2047 तक विकसित बनाने का जो संकल्प है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं।■

भारतीय रेल / Indian Railways

पत्रिका की सदस्यता एवं पत्रिका नहीं मिलने की शिकायत हेतु

फोन या व्हाट्सएप करें

92205 05349

सोमवार से शुक्रवार (सुबह 10 से 5 बजे तक)

Email: bmpr310rb@gmail.com, irbrhelp@gmail.com

अपना ज्ञान टटोलें

1. हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 'अमृत भारत एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाई ?

(क) बिहार ☐ (ख) उत्तर प्रदेश ☐

(ग) तमिलनाडु ☐ (घ) झारखंड ☐

2. भारत की सबसे लंबी टनल किस रेल परियोजना के अतंर्गत बनी है ?

(क) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक ☐ (ख) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ☐

(ग) मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर ☐ (घ) सेवोके-रंगपो रेल परियोजना ☐

3. बिहार में शुरू की गई 'नमो भारत रैपिड रेल' किन दो शहरों को जोड़ती है ?

(क) वैशाली-मुजफ्फरपुर ☐ (ख) हाजीपुर-पटना ☐

(ग) जयनगर-पटना ☐ (घ) समस्तीपुर- पटना ☐

4. 4 तथा 9 अप्रैल, 2025 को कैबिनेट ने कितनी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी ?

(क) 8 ☐ (ख) 5 ☐

(ग) 12 ☐ (घ) 7 ☐

5. दिनांक 6 अप्रैल, 2025 को नए पांबन ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ?

(क) उपराष्ट्रपति ☐ (ख) रेलमंत्री ☐

(ग) राष्ट्रपति ☐ (घ) प्रधानमंत्री ☐

6. भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट तकनीक वाला रेलवे समुद्री ब्रिज का नाम क्या है ?

(क) नया पांबन ब्रिज ☐ (ख) वेम्बनाड रेल ब्रिज ☐

(ग) नेहरू सेतु रेल ब्रिज ☐ (घ) चिनाब रेल ब्रिज ☐

7. पुराना पांबन ब्रिज किस वर्ष में शुरू हुआ ?

(क) 1915 ☐ (ख) 1914 ☐

(ग) 1947 ☐ (घ) 1954 ☐

8. नए पांबन ब्रिज की वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की ऊँचाई कितनी है ?

(क) 57 मीटर ☐ (ख) 75 मीटर ☐

(ग) 78 मीटर ☐ (घ) 72 मीटर ☐

9. नया पांबन ब्रिज किस राज्य में है ?

(क) उड़ीसा ☐ (ख) केरल ☐

(ग) तमिलनाडु ☐ (घ) महाराष्ट्र ☐

10. रेल यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर ?

(क) 139 ☐ (ख) 132 ☐

(ग) 131 ☐ (घ) 137 ☐

1. (ख) 2. (ख) 3. (ग) 4. (ख) 5. (ख) 6. (ख) 7. (ख) 8. (ग) 9. (ग) 10. (क)

TRANSFORMING RAILWAYS

THROUGH EXPERIENCE AND INNOVATION

India's 1st Private Railway Engineering Consulting Company



- Four Decades of Industry Experience
- Proven Success in Timely Delivery of Complex Projects
- Practical Solutions Using Latest Technology
- Strong Commitment to Sustainability
- Comprehensive Services Across Railway Sectors

BARSYL
we innovate



Balaji Railroad Systems Private Limited

"BARSYL Towers", Plot No. 3 Sitaram Nagar, Staff Road, Secunderabad - 500009 Telangana, INDIA.

+91 40 27847804 / 06 mail@barsyl.in www.barsyl.in

IRIS Certification
AAR M-1003
Daulat Ram ENGINEERING

PRIME MOVERS FOR RAIL, MINING & URBAN MOBILITY

- Traction Motors / Alternators
- Air Conditioners
- Cooling Fans / Blowers
- Dynamic Brake Resistors
- Pantographs
- E- Buses
- Auxiliary Generators



10/2, NH-12, Simrai, Post Obedullahganj, Distt. Raisen, Near Bhopal, 464993, India
+91 7480 350001 to 350030 +91 8889983336 info@daulatram.org www.daulatram.com

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोए
रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एकमात्र हिंदी मासिक पत्रिका



भारतीय रेल

की सदस्यता अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

अब ई-पत्रिका भी उपलब्ध

www.irctctourism.com/IRBRmag/#/home/hn

क्यू आर कोड स्कैन करें

सदस्यता शुल्क

मद		ऑफलाइन सदस्यता शुल्क (₹)	ऑनलाइन सदस्यता शुल्क (₹)	ई-पत्रिका सदस्यता शुल्क (₹)
एक प्रति (मासिक अंक)		20	-	-
एक प्रति (विशेषांक)		70	-	-
वार्षिक सदस्यता (सर्व साधारण)	एक वर्ष	250	263	130
	दो वर्ष	460	483	230
	तीन वर्ष	675	709	340
वार्षिक सदस्यता (रेलकर्मी)	एक वर्ष	200	210	100
	दो वर्ष	370	389	190
	तीन वर्ष	540	567	270
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) सी-मेल द्वारा		1,250	1,313	----
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) एयर-मेल द्वारा		2,500	2,625	----

(सदस्यता शुल्क में वार्षिक विशेषांक भी शामिल है।)

सदस्यता फॉर्म

नाम .....

पता .....

..... पिन कोड .....

मोबाइल ..... ई-मेल .....

पहचान पत्र संख्या (यदि रेल कर्मचारी है तो): ..... वैधता की तारीख .....

ऑफलाइन भुगतान का माध्यम

I) एम.ओ./आई.पी.ओ/डी.डी. व्यापार प्रबंधक के पक्ष में कमरा नं0 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
II) नगद जमा कराने हेतू : कमरा नं0 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: व्यापार प्रबंधक, कमरा नं. 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001,
टेलीफोन: 011-47845089, 45089 (रेल) **bmpr310rb@gmail.com**

पंजीयन संख्या : दिल्ली पोस्टल नं. डी.एल. (एन.डी.)-11/6031/2024-25-2026
आर.एन.आई रजिस्टर्ड नं. 14427/1960
ISSN 2457-0001
दिनांक 08 को प्रकाशित तथा दिनांक 10-11 को प्रेषित



विज्ञापन दरें

विवरण	सामान्य अंक (मासिक दरें)		विशेष अंक (वार्षिक अंक)
	सामान्य दरें	अनुबंधित दरें*	
बैक कवर	₹22,000	₹20,000	₹25,000
सेकेण्ड कवर	₹19,000	₹17,000	₹22,000
थर्ड कवर	₹19,000	₹17,000	₹22,000
पूरा पृष्ठ (विशेष स्थिति, जैसे टेक्स्ट के बाद में)	₹16,000	₹15,000	₹18,000
पूरा पृष्ठ	₹15,000	₹14,000	₹17,000
आधा पृष्ठ	₹9,000	₹8,000	₹11,000
सेंटर स्प्रेड (दो पेज इकट्ठे)	₹28,000	₹25,000	₹32,000

* तीन महीने या इससे अधिक अवधि के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाने का अनुबंध करने पर लागू।
• उपरोक्त दरों के साथ 5% जीएसटी, आइजीएसटी प्राप्य होगी।

भुगतान का माध्यम

'व्यापार प्रबंधक, भारतीय रेल, नई दिल्ली'
के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, चेक लिखें अथवा एनईएफटी के द्वारा

तकनीकी विवरण

पत्रिका का आकार : 28X20.5 सेमी, छपाई क्षेत्र : 23X16.5 सेमी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

ललित कुमार धनकड़, व्यापार प्रबंधक
310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन : 011- 47845378, 23382531, email : bmpr310rb@gmail.com

मुद्रक व प्रकाशक : **ललित कुमार धनकड़** द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के लिए मैसर्स विबा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 में मुद्रित व 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। संपादक : **योगेश अवस्थी**